



TIMES OF PEDIA

NEW DELHI Page 12 Price Rs. 3.00

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इंसाफ़ की डगर पर

www.timesofpedia.com

WEEKLY HINDI, ENGLISH, URDU

WED 24 DEC - TUE 31 DEC 2025

VOL. 13. ISSUE 52

RNI No. DELMUL/2012/47011

नमो भारत की सुरक्षा होगी अभेद्य



भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड रीजनल रेल सेवा नमो भारत अब और सुरक्षित होने जा रही है। उार प्रदेश पुलिस की स्पेशल सिक्वोरिटी फोर्स (P SSF) के लगभग जवान इस कॉरिडोर की सुरक्षा

इयूटी संभालेंगे। उनकी ट्रेनिंग का जिम्मा लिया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्वोरिटी फोर्स (CISF) ने, जो एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो और संसद भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा करती है।

बिना QR कोड ई रिक्शा बंद नए साल से नया नियम

ई-रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर है। एनसीआर के गाजियाबाद शहर में जनवरी से बिना क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शा नहीं चल सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ई-रिक्शा चालक दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराकर अपना क्यूआर कोड मुफ्त प्राप्त कर लें। डीसीपी ट्रेफिक त्रिगुणगु बिसेन के अनुसार, शहर

की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हर ई-रिक्शा को एक यूनिक क्यूआर कोड से जोड़ा जा रहा है। इस क्यूआर कोड में ई-रिक्शा चालक का नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, वाहन पंजीकरण और परमिट से जुड़ी जानकारी दर्ज रहेगी।

निवेश के नाम पर 22 लाख की ढगी आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली : दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

इस मामले में दो गिरफ्तारी भी की हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह मामला एक फर्जी स्टॉक-ट्रेडिंग एप्लिकेशन

घोटाले से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए लालच दिया गया था। यह ग्रुप खुद को शेयर बाजार से जुड़ा एक असली चर्चा मंच (forum) बताता था। नवंबर को दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि पीड़ित

को 'Stan Chart Dialogue Forum L' नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था।

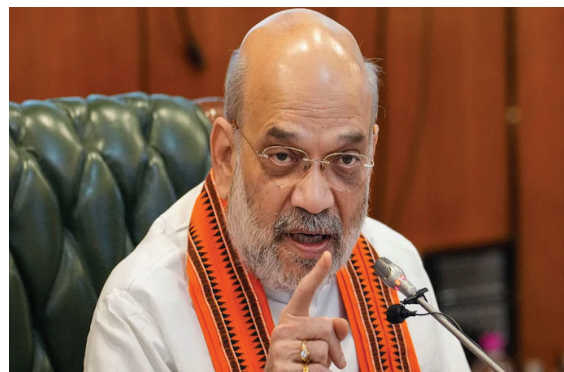
दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस ग्रुप में पांच एडमिन थे जो डीमैट शेयरों (demat shares) पर चर्चा करते थे। ग्रुप की एक एडमिन, यालिनी गुना गु (Yalini Guna) ने 'SCIIHNW' नाम के एक ऐप के माध्यम से निवेश योजना की पेशकश की और शेयर दिलाने का दावा किया। पीड़ित ने दिए गए लिंक से ऐप इंस्टॉल किया और निवेश किया, जिसके बाद उसके साथ ठगी हुई।

77 का आंकड़ा तय करेगा बंगाल में भाजपा की सरकार

नई दिल्ली : जैसे-जैसे ये साल खत्म हो रहा है नए साल के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव भी करीब आ रहे हैं। भाजपा अभी से ही बंगाल में प्रचार में जुट गई है। पीएम मोदी से लेकर शाह और तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल का दौरा कर रहे हैं।

अब सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल की धरती पर भाजपा वहीं चमत्कार दोहरा पाएगी जो उसने राष्ट्रीय स्तर दोहराया था? ख से फफ सीट वाली उस शानदार पारी को अब बंगाल की पिच पर खेलना है। ये बात अलग है कि यहां टीम अलग है, मैच राष्ट्रीय नहीं बल्कि राज्य स्तर का है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को कोलकाता में थे। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की इस पिच पर भाजपा धुरंधर बल्लेबाज साबित होगी। शाह ने भाजपा की सीटों और वोट प्रतिशत



की यात्रा का का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी ये भविष्यवाणियां हवा में नहीं हैं, बल्कि ठोस आधार पर टिकी हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में खूब के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके लिए पार्टी के पास मजबूत नींव है। यह दावा पार्टी के बढ़ते जनाधार और संगठनात्मक मजबूती पर आधारित है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लंबे शासन के बाद भाजपा इसे बड़ा अवसर मान रही है।

बंगाल प्रवास के दूसरे दिन कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते

हुए शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की लंबी वोट यात्रा रही है।

अमित शाह ने कहा कि यह बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को कभी सिर्फ 5 सीट मिली थीं, वह पार्टी पांच साल के अंदर खूब सीटों पर पहुंच गई है।

बंगाल प्रवास के दूसरे दिन कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल की पूरी डेमोग्राफी ही बदल गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र के लगातार अनुरोध के बावजूद भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए

बंगाल सरकार जमीन नहीं दे रही है।

बंगाल सरकार चाहती है कि घुसपैठ ऐसे ही जारी रहे ताकि उनकी सभा चलती रहे। शाह ने स्पष्ट कहा कि आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में घुसपैठ ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार बनने पर न सिर्फ बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह सील किया जाएगा बल्कि घुसपैठियों को भी चुन-चुन कर वापस उनके देश भेजा जाएगा।

गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि भाजपा बंगाल में दो तिहाई बहुमत से जीतेगी और अप्रैल में चुनाव के बाद अगली सरकार बनाएगी। 77 के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा कि मतुआ समुदाय को इससे कोई डरने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक भाजपा है, ममता बनर्जी मतुआ शरणार्थियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

पक्के घर गाड़ी वालों को नहीं मिलेगा पीएम आवास सेटलाइट से निगरानी

मुरलीपहाड़ी (जामताड़ा) । PM Awas Yojana का लाभ अब सिर्फ जरूरतमंद परिवार को ही मिल पाएगा। अब ऐसा नहीं कि घर में पहले से पक्का मकान हो और उनका नाम सर्वे सूची में पंचायत सचिव के द्वारा डाल दिया गया हो तो उन्हें इतनी आसानी से पीएम आवास का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसकी निगरानी सरकार सेटलाइट के माध्यम से की जा रही है।

इस मामले को लेकर

सोमवार को नारायणपुर प्रखंड के शहरपुर पंचायत में प्रतीक्षा सूची में शामिल कुछ परिवारों की जांच की गई। जांच दल की अगवाई स्वयं बीडीओ देवराज गुप्ता कर रहे थे। जांच के क्रम में उक्त पंचायत में वास्तविक में कई परिवार अपवर्जन मानक में नहीं पाए गए।

वे या तो पहले से पक्के मकान में थे या फिर अन्य सुविधाओं से लैस थे। बीडीओ देवराज गुप्ता ने बताया कि यह

जांच सरकार द्वारा भेजी गई संदिग्ध सूची के अनुसार की गई है। जिसमें सोमवार को कई परिवार गरीबी रेखा से ऊपर पाए गए।

उन्होंने बताया जो कच्चे मकान में रहने वाले परिवार हैं, जिनकी संपत्ति कम है और चार पहिया वाहन नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं, जिनके पास 1 एकड़ जमीन से अधिक की संपत्ति है, उन्हें तो किसी भी सूत्र में आवास की सुविधा नहीं

दिया जाएगा।

यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए है। इसकी जांच प्रत्येक पंचायत में अभी होगी। इसकी शुरुआत अभी शहरपुर से की गई है। इस पंचायत में ऐसे कच्चे परिवार जिनका नाम पीएम आवास के प्रतीक्षा सूची में शामिल है, उनकी जांच होनी है। इसीलिए जांच दल का गठन भी किया गया है। इसमें कनीय अभियंता सहित अन्य कर्मी शामिल रहेंगे।

क्रिसमस के दिन देशभर के गिरजाघरों के सामने जो कुछ हुआ वो भारत के खिलाफ साज़िश का हिस्सा हैलेकिन क्यों आइये समझते हैं



Ali Aadil Khan
Editor

लोकतंत्र में शासक वर्ग की चुप्पी सहमति के रूप में देखी जा रही है, और यही नफरत फैलाने वालों का हौसला बढ़ा रही है, एक राजनितिक वर्ग को कुछ बरसों के लिए शासन मिल सकता है, लेकिन अवाम और देश के लिए यह बड़ी चिंता का विषय है.

पूरी दुनिया में 195 Recognised देश हैं, इनमे से 120 इसाई मुल्क हैं. क्रिसमस का त्यौहार दुनिया में पूरी आस्था और श्रद्धा से मनाया जाता है और प्रेम, करुणा और शांति का संदेश लेकर आता है, भारत में भी हमेशा से आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक रहा है।

लेकिन हाल के दिनों में भारत में धार्मिक नफरत और उन्माद काफी बढ़ा है, जिससे देश के सम्मान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट आई है. पूरे भारत में जगह जगह क्रिसमस के अवसर पर गिरजाघरों के सामने हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा लगाए गए धर्मसूचक और अपमानजनक नारों और हनुमान चालीसा के पाठ ने देश की सामूहिक चेतना और संवैधानिक मान्यताओं को धूमिल किया है। इंग्लैंड का telegraph अखबार ने लिखा कि भारत में ईसाईयों को निशाना बनाया जा रहा है और हमलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, देखें अभिसार शर्मा की यह रिपोर्ट

हालाँकि प्रधानमंत्री दिल्ली के गिरजाघर गए और प्रार्थना में शरीक भी हुए. अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से इस बात का notice भी लिया गया. लेकिन उनका कहना था कि PM मोदी आये उनका शुक्रिया लेकिन देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के लोग जगह जगह नफरती और उन्मादी गुप्स जो खुले आम जुर्म

कर रहे हैं उनको सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है. उनके खिलाफ कोई सख्त क़दम क्यों नहीं उठाते यह उनकी शिकायत थी

क्रिसमस के दिन भारत में नफरत का यह भोंडा तमाशा केवल ईसाई समुदाय का अपमान नहीं है, बल्कि यह उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती है, जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है, यानी अनेकता में एकता, जो हमारी पहचान भी है.

भारतीय संविधान की बुनियाद धार्मिक स्वतंत्रता और समानता पर रखी गई है। हमारे संविधान की यह खूबसूरती है कि हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार का अधिकार देता है। कुछ पाखंडी संविधान के ज़रिये दी गई इस आज़ादी से डरते हैं, शायद इस लिए कि उनको अपनी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं पर भरोसा नहीं है, रखना चाहिए.

ऐसे में कुछ उन्मादियों द्वारा किसी धार्मिक स्थल के सामने जाकर नारेबाज़ी करना, ख़ौफ़ का माहौल बनाना और धार्मिक आस्था को निशाना बनाना, किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर किसी क़ौम को अपनी धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति पर सही होने का भरोसा है तो उसको चाहिए उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारे और अगर किसी मज़हब से इख़्तलाफ़

है तो Healthy डिबेट एक अच्छा रास्ता हो सकता है, लेकिन उसके लिए तथ्य चाहिए बहस और उन्माद नहीं.

सवाल यह उठ रहा है कि देश में लगातार बढ़ता सभा द्वारा प्रायोजित नफरत का यह चलन आखिर किस उद्देश्य से किया जा रहा है? किसके फायदे के लिए किया जा रहा है? क्योंकि समाज और देश तो कमज़ोर हो रहा है. जवाब है देश के दुश्मनों के अजेंडे को आगे बढ़ाने और सभा पर क़ब्ज़ा जमाये रहने के लिए यह सारे कृत्य होते हैं.

नफरत और उन्माद के इस पूरे प्रकरण में सबसे चिंताजनक पहलू प्रशासन की भूमिका को लेकर है। यदि ऐसी घटनाओं पर समय रहते प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती, तो यह संदेश सीधे तौर पर जाता है कि कानून सबके लिए समान नहीं है। और इन्साफ़ में सौतेलापन समाज और देश को खा जाता है.

लोकतंत्र में शासक वर्ग की चुप्पी सहमति के रूप में देखी जा रही है, और यही नफरत फैलाने वालों का हौसला बढ़ा रही है, एक राजनितिक वर्ग को कुछ बरसों के लिए शासन मिल सकता है, लेकिन अवाम और देश के लिए यह बड़ी चिंता का विषय है.

भारत की ताकत इसकी विविधता में है। यहाँ हर धर्म, आस्था और त्योहार इस देश की साज़ा विरासत का हिस्सा है जो मुल्क की खूबसूरती को दोबाला

करती है. आज क्रिसमस के दिन भारत में ईसाई चर्चों को निशाना बनाया जाना कल प्रवासी भारतियों के लिए विदेशों में बढ़ती परेशानियों का सबब बनेगी. साथ ही हमारी विदेश नीतियों को और कमज़ोर करेगी। इसलिए यह नफरती और उन्मादी मुद्दा किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश की सामाजिक और कूटनीतिक भविष्य का है।

आज ज़रूरत इस बात की है कि समाज के सक्षम ज़िम्मेदार वर्ग, राजनीतिक दल, धार्मिक नेता और सिविल सोसायटी स्पष्ट शब्दों में कहें कि देश में नफरत, अपमान और उकसावे की राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा के भीतर; असहमति हो सकती है, लेकिन संविधान के दायरे में। क्रिस्टमस हमको इस बात की याद दिलाता है कि संसार में कहीं भी जब दूत नामी कोई फूल खिलता है, तो उसकी सुगंध पूरे संसार में फैल जाती है। और यह फूल खुद अपने लिए नहीं खिलता, बल्कि उसकी खुशबू पूरे समाज और संसार को सुगन्धित और मनमोहक बना देती है। और ऐसे ही खिले हुए फूलों में से एक अत्यंत प्यारा फूल थे जीसस, यानी ईसा मसीह, जो फिर इस दुर्गन्धित संसार को अमन, मोहब्बत और खुशबू से महकाने इस धरती पर उतरेंगे।

किस मुँह से करें उन के तगाफुल की शिकायत खुद हम को मोहब्बत का सबक याद नहीं है

राष्ट्रमंडल खेलों के बहाने क्या अहमदाबाद बन पाएगा कर्णावती

उमेश चतुर्वेदी

राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी वर्ष के आयोजन की ज़िम्मेदारी अहमदाबाद को मिलने के बाद एक बार फिर उसका नाम बदलकर कर्णावती करने को लेकर सोशल मीडिया पर मांग तेज हो गई है। तर्क दिया जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन तक गुजरात की पहली राजधानी को कर्णावती के नाम से जाना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है, जब इस शहर का नाम बदलने की मांग हो रही है। जब गुजरात के सहोदर राज्य महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने कई शहरों के नाम बदले, तब भी यह मांग उठी थी। लेकिन तब इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का जोर भारत के प्राचीन रूप और नाम पर रहा है, फिर गुजरात की सभा पर भाजपा तकरीबन तीन दशक से काबिज है, इसकी वजह से शहर को पुराने नाम की पहचान दिलाने की चाहत रखने वाले रह-रहकर मांग करते रहे हैं।

गुजरात के इस प्रमुख नगर को पहले कर्णावती के ही नाम से जाना जाता था। दस्तावेजों के मुताबिक, इसकी स्थापना सोलंकी शासक कर्णदेव ने की थी। उसी के नाम के चलते इसे कर्णावती कहा जाता था। लेकिन बाद में वहां सुल्तान अहमद शाह ने आक्रमण किया और कब्जे के बाद उसने इस शहर के बगल में 'अहमदाबाद' बसाया। कर्णावती नाम करने की मांग के पीछे

इस शहर को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जोड़ने की चाहत से प्रेरित है। कुछ वैसे ही, जैसे उत्तर प्रदेश में फैजाबाद को बदलकर अयोध्या, मुगलसराय को बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर, इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है।

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गौरवशाली अतीत से जुड़ने और उसकी संज्ञाओं को बहाल करने का दौर तेज हो गया है। अयोध्या में राममंदिर, वाराणसी में काशी-विश्वनाथ कॉरीडोर और उज्जैन में महाकाल कॉरीडोर बनने के बाद पुनरुत्थानवादी सोच और प्रक्रिया को और बल मिला है। ऐसे में अहमदाबाद को पुराने कर्णावती नाम से जानने-पुकारने की इच्छा होना अचरज की बात नहीं है। कर्णावती नाम करने को लेकर कभी इसी शहर के एलिसब्रिज से विधायक और अब गांधीनगर से सांसद गृहमंत्री अमित शाह और अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा सदस्य रहे हंसमुख भाई पटेल नकार चुके हैं। यह बात और है कि कभी हंसमुख पटेल खुद भी कर्णावती नाम करने के लिए अभियान चला चुके थे। उन्होंने खुद नाम बदलने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन इसे नकार दिया गया था। बाद में उन्होंने ही शहर को हेरिटेज सिटी यानी विरासत शहर का दर्जा देने की मांग की थी। इसके बाद वे कर्णावती नाम किए जाने की मांग

से पीछे हट गए थे। तब उन्होंने कहा था कि अब अगर अहमदाबाद शहर का नाम बदलकर कर्णावती किया गया तो उसे वर्ल्ड हेरीटेज सिटी का दर्जा मिलना मुश्किल हो जाएगा।

गुजरात के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा था कि राज्य सरकार अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने पर विचार कर रही है। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी ऐसा कहते रहे। तब उनकी राय सामने आने के बाद अहमदाबाद के इतिहास को लेकर नई बहस छिड़ गई थी। इसी तरह जब से अहमदाबाद को राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का ज़िम्मा मिला है, एक बार फिर यही बहस तेज हो गई है।

अहमदाबाद ही कर्णावती था, इसकी जानकारी कई ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलती है। ऐसी ही एक पुस्तक है, गुजरात विश्वविद्यालय में फ़ारसी के प्रमुख रहे छोटूभाई नायक की किताब 'हिस्ट्री ऑफ़ इस्लामिक सल्तनत इन गुजरात'। इसमें छोटू भाई नायक ने बताया है कि गुजरात के पहले स्वतंत्र शासक मुज़फ़्फ़रशाह ने अपने चार लड़कों को दरकिनार करते हुए अपने पोते अहमद शाह को अनहिलवाद के सिंहासन पर बैठा दिया था। जिसे आज हम पाटन के नाम से जानते हैं। इसी मुज़फ़्फ़र शाह के पांच बेटे थे, फ़िरोज़ ख़ान, हैबत ख़ान, सादत ख़ान, तातार ख़ान और शेर ख़ान। जिस अहमद शाह

ने अहमदाबाद बसाया, वह तातार ख़ान का बेटा था। अहमद शाह के चाचाओं को इस बात का मलाल रहा कि राज्य में उन्हें हिस्सा नहीं मिला। गुजरात के इतिहास पर अंग्रेज़ लेखक एडवर्ड लाइव बेले की मशहूर किताब है, 'द लोकल मौह्यडन डायनेस्टीज़: गुजरात'। इसमें उन्होंने मुज़फ़्फ़रशाह परिवार के संघर्ष पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में बताया गया है कि फ़िरोज़ ख़ान का बेटा और अहमद शाह का चचेरा भाई मौदूद तब बड़ोदा का गवर्नर था। मौदूद ने अपने पिता फ़िरोज़ ख़ान के साथ मिलकर अहमद शाह के ख़िलाफ़ बगावत छेड़ने की तैयारी की और अपने साथ अमीर मुसलमानों को मिलाना शुरू किया। इस पुस्तक के मुताबिक, तत्कालीन दो हिंदू सरदारों, जीवनदास खत्री और प्रयागदास ने भी फ़िरोज़ ख़ान का साथ दिया। छोटू भाई शाह की पुस्तक के अनुसार, मालवा के सुल्तान हुशांग शाह ने भी अहमद शाह के ख़िलाफ़ बगावत में फ़िरोज़ ख़ान का साथ दिया था। अहमद शाह के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही सेना की अगुआई मौदूद के हाथ थी, उसने जीवनदास को अपना वज़ीर घोषित कर दिया। जीवनदास ने पाटन पर हमले की सलाह दी। लेकिन कई ने इसका विरोध किया। कुछ लोग ऐसे भी रहे, जिन्होंने समझौते का प्रस्ताव रखा था। लेकिन दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने पलट कर अहमद शाह से मिल गए।

अहमदाबाद ही कर्णावती था, इसकी जानकारी कई ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलती है। ऐसी ही एक पुस्तक है, गुजरात विश्वविद्यालय में फ़ारसी के प्रमुख रहे छोटूभाई नायक की किताब 'हिस्ट्री ऑफ़ इस्लामिक सल्तनत इन गुजरात'।

हसीना को उखाड़ फेंकने वाली छात्र पार्टी में ही फूट, जमात की शरण में पहुंची

ढाका : बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को प्रस्तावित आम चुनावों से पहले छात्र आंदोलन से बनी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) गंभीर राजनीतिक संकट से जूझ रही है। 2024 में शेख हसीना विरोधी प्रदर्शनों के बाद उभरी इस पार्टी को कभी बांग्लादेश की पारंपरिक राजनीति से बाहर एक तीसरी ताकत के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि पार्टी या तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) या फिर बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के साथ समझौता करने को मजबूर दिख रही है।

NCP वही राजनीतिक दल है, जिसे उन छात्र नेताओं ने मिलकर खड़ा किया था जिन्होंने 2024 में हुए आंदोलन के बाद मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने का रास्ता साफ किया था। पार्टी पर लंबे समय से यूनुस के संरक्षण में होने के आरोप लगते रहे हैं। दूसरी ओर, अवामी लीग फिलहाल प्रतिबंधित होने के कारण चुनावी दौड़ से बाहर है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, NCP को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भल ही पहचान मिली हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका सांगठनिक विस्तार बेहद सीमित रहा है। ५५ सीटों वाली संसद (जतिया संसद) में सभी सीटों पर लड़ने की तो बात दूर, पार्टी अब महज ५ से ५ सीटों तक की सौदे बाजी तक सिमटती दिख रही है। ढाका के रिपोर्ट के अनुसार, NCP और जमात-ए-इस्लामी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि, जमात ने NCP की सीटों की मांग को अव्यावहारिक बताया है, जिसके बाद चर्चा सीटों पर आकर रुक गई है।

इन संभावित गठबंधनों ने NCP के भीतर गहरी फूट पैदा कर दी है। पार्टी के एक धड़े का मानना है कि जमात के साथ जाना चुनावी अस्तित्व के लिए जरूरी है, जबकि दूसरा धड़ा BNP के साथ समझौते का पक्षधर है- खासकर BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी के बाद इसी खींचतान के बीच NCP के संयुक्त सदस्य सचिव और चटग्राम इकाई के प्रमुख



मीर अरशादुल हक ने इस्तीफा दे दिया। वह पार्टी के भीतर जमात विरोधी गुटों के प्रमुख चेहरे माने जाते थे। द डेली स्टार के मुताबिक, उनका जाना पार्टी के अंदरूनी संकट की गंभीरता को दिखाता है।

जमात-NCP बातचीत को लेकर आरोप भी सामने आए हैं कि जमात प्रत्येक सीट के बदले NCP को करोड़ टका दे सकती है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए छात्र आंदोलन से जुड़े नेता अब्दुल कादर ने कहा - युवा राजनीति की कब्र खोदी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि समझौते की सूरत में NCP बाकी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी और जमात का समर्थन करेगी।

NCP पर लंबे समय से किंग्स पार्टी का तमगा लगा है। आलोचकों का कहना है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने पार्टी को असामान्य राजनीतिक संरक्षण दिया- कैबिनेट में सलाहकार पद, सुधार आयोगों में नियुक्तियां और चुनावी प्रक्रिया को टालने जैसे कदम

इसी धारणा को मजबूत करते हैं। हालांकि, पार्टी ने कई बार यूनुस पर भी BNP के पक्ष में झुकाव रखने के आरोप लगाए हैं, जिससे दोनों के रिश्तों की असहज और लेन-देन वाली प्रकृति उजागर होती है।

NCP की अंदरूनी कलह का असर उसके नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अलायंस पर भी पड़ा है, जिसमें अमार बांग्लादेश पार्टी और राज्य सुधार आंदोलन शामिल हैं। गठबंधन की शर्तों कि वे BNP और जमात - दोनों से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन अब उस समझौते के टूटने के संकेत मिल रहे हैं।

बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। लंबे समय से लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान दिसंबर में बाद स्वदेश लौट आए। उनकी वापसी पर लाखों समर्थकों ने ढाका में भव्य स्वागत किया, जिसने पूरे देश की सुर्खियां बंटो लीं। इसी बीच, छात्रों द्वारा गठित नेशनल सिटिजन पार्टी

की हालिया भारत-विरोधी प्रदर्शनों की कोशिशें फीकी पड़ती दिख रही हैं।

तारिक रहमान, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के प्रमुख चेहरे हैं। उनका विमान ढाका के हजरत शाहजहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। एयरपोर्ट से उनके निवास तक का रोड शो लाखों कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। अनुमान है कि करीब लाखों लोग सड़कों पर उतरे। तारिक ने अपने पहली सार्वजनिक संबोधन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मशहूर लाइन आई हैव ए ड्रीम का जिक्र करते हुए कहा- मेरे देश के लिए एक प्लान है।

तारिक की वापसी ऐसे समय में हुई है जब देश में हालिया हिंसा और भारत-विरोधी प्रदर्शनों ने माहौल गरमाया हुआ था। दिसंबर में छात्र नेता शरीफ ओसमान हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में भारत-विरोधी नारे लगे और कई संस्थानों पर हमले हुए। एनसीपी के नेता इन प्रदर्शनों में सक्रिय थे और भारत पर आरोप लगाते रहे। एनसीपी इन प्रदर्शनों से सुर्खियां बंटोने की कोशिश कर रही थी।

लेकिन तारिक रहमान की भव्य वापसी और बीएनपी की भीड़ ने एनसीपी की इन कोशिशों को पीछे धकेल दिया है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश में हिंसा का दौर भी तेज हुआ है। अंतरिम सरकार के सभा में आने के बाद से अब तक भीड़ हिंसा में लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में एक हिंदू कपड़ा मजदूर दीपूचंद्र दास की कथित ईशनिंदा के आरोप में हत्या ने हालात को और गंभीर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरिम सरकार ने शांति की अपील की है, लेकिन चुनावी माहौल पर इसका साया गहराता जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर NCP पूरी तरह विभाजित होती है या किसी बड़े दल में विलीन हो जाती है, तो यह न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि बांग्लादेश की युवा राजनीति और आगामी चुनावों के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

NOTICE:

Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

ट्रंप-ज़ेलेंस्की की मुलाकात के पहले रुस ने बरपाया कहर, धुआँ-धुआँ हुआ कीव

रुस और यूक्रेन का युद्ध निर्णायक मोड़ पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके यूक्रेनी समकक्ष के बीच युद्ध विराम के विषय

पर जल्द ही फ्लोरिडा में चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पहले रूसी मिसाइलों और ड्रोन्स ने कीव और उसके आस पास के क्षेत्रों में

जमकर कहर बरपाया है। रात भर हुए इन हमलों की वजह से कीव यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए।

कीव और आस पास के इलाकों में हुए धमाकों के बाद यूक्रेनी सेना ने भी बयान जारी किया। सेना ने टेलीग्राम एप पर बताया कि रूस की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं। वायुसेना के अनुसार, रूसी ड्रोन राजधानी के साथ-साथ पूर्वोत्तर और दक्षिणी



क्षेत्रों को निशाना बना रहे थे।

इसकी वजह से कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी रहा। दूसरी तरफ, रूस की ओर से अभी तक इन हमलों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इन हमलों से पहले यूक्रेन

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को ट्रंप के साथ होने वाली अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी दी थी।

उन्होंने कहा था कि इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा यह होगा कि लड़ाई के रुकने के बाद

किस पक्ष के नियंत्रण में कौन सा इलाका रहेगा। ट्रंप ने भी इस मुलाकात को लेकर काफी उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि में रूस के आक्रमण के साथ शुरू हुआ यह युद्ध अभी भी यूरोप की सांस अटकाए हुए है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है।

दोनों देशों के बीच में जारी भीषण लड़ाई के बीच दोनों ही पक्ष लगातार शांति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया की मानें तो क्षेत्रीय नियंत्रण का विषय इस शांति समझौते के बीच में सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है। दोनों ही देश जमीन को नहीं छोड़ना चाहते। इसके अलावा सूत्रीय प्रस्ताव पर - फीसदी काम पूरा हो चुका है।

From Right based MNREGA to allotment-based G-RAM-G



Ram Puniyani

Around the time of Rath Yatra when BJP began to rise, it projected itself as 'party with a difference'. As the electoral power of this party started going up many thinkers and writers were not much worried as they saw in BJP, another side of the then ruling Congress. Its colours started coming up when even the dominant partner in the NDA with Vajpayee as the leader. It came to power twice for short periods lasting for 13 days and 13 months before it ruled for nearly 6 years with Vajpayee as the Prime minister. Many of those writers did see the 'difference' of this party as stifling of democratic norms were very much in the air even during that time.

The period of UPA I in particular was marked by a series of schemes based on the concept of 'rights'. Right to information, health, food, education and what have you. Probably this was the peak point of Indian democracy as average and poor citizens' rights came to the forefront. The social movements put adequate pressure to ensure that the Government comes forward not only to fulfil its constitutional

duties and start the schemes based on the concept of rights but also to ensure that the empowerment of the deprived sections is upheld.

With the third term of the Narendra Modi Government, the core agenda of communal politics is becoming more apparent. Nationalism was constructed around Hindu identity, concentration of power with the central government, undermining the very concept of federal state and that 'India is a Union of states'. Side tracking the schemes structured around Rights and bringing forth the schemes that come more as policies of the authoritarian state, where the state is dishing out schemes to the people. Schemes are coming up where decentralization is being done away with.

There is a perception that BJP-RSS are just against Muslims. The truth is that it is against the marginalized and labouring section of masses, Dalits, workers, Adivasis and women in particular. We have witnessed the 'farm laws' which the peasants opposed were stubbornly introduced. For the withdrawal of these peasants had to sacrifice nearly 600 lives before they could be repealed. We recently saw the labour codes which take away the hard-earned rights of labouring masses. And now we are seeing a similar process against farm

workers as MNREGA is being scrapped and VB G-RAM-G is being brought in.

The Central Government is scrapping Mahatma Gandhi National Rural Employment Act (MNREGA) and bringing in Viksit Bharat – Guarantee For Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025 (VB-G RAM G). A good mix of English and Hindi/Urdu words to make an acronym RAM, the Lord who has been an important identity issue around which BJP has developed its divisive politics.

The major factors the new bill aims are, first to increase the number of days from 100 to 125 days. It may sound an improvement on the existing 100 days in MNREGA. As such MNREGA is based on the demand of the unemployed citizen. As per MNREGA Sangharsh Morcha, "MGNREGA establishes a statutory right to work that is demand-driven and universal i.e. any person willing to do unskilled manual work in any rural area must be provided work. But under the VB-G RAM G Bill, Section 5(1) states "the State Government shall, in such rural areas in the State as notified by the Central Government, provide to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work, not less than 125 days of guaranteed employment."

The cat is out of the bag. The Central Government will be notifying authority as to in which areas it will apply. It reduces the

universal nature of the scheme to the areas notified by the Central Government. Section 4(5) of the VB-G RAM-G Bill states "The Central Government shall determine the State-wise normative allocation for each financial year, based on objective parameters as may be prescribed by the Central Government," while Section 4(6) further provides that "Any expenditure incurred by a State in excess of its normative allocation shall be borne by the State Government in such manner and by such procedure as may be prescribed by the Central Government."

The logic off MNREGA is put upside down as MGNREGA funding is based on demand to a supply-driven system. In G-RAM-G demand has to conform to a predetermined budget.

In MNREGA 90% of funds were to come from Central Government, while G-RAM-G, in most states Centre will give only 60% of funds, and the remaining 40% has to come from the state Governments, which are already starved of funds. The states in turn due to paucity of funds may not register the demands for employment by many. Gram Sabhas were doing the planning at local level, in contrast now G-RAM-G this provision is overturned by Schedule 1, clause 6(4) of the VB-G RAM G Bill which states that "Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack shall guide States, Districts and Panchayati Raj Institutions in identifying priority infrastructure

gaps, standardising work designs, and ensuring that public investments contribute measurably to saturation outcomes at the Gram Panchayat, Block and District levels." This is a severe undermining of the Panchayati Raj concept, developed and implemented with changes towards democratization so far.

"Section 6(2) of VB-G RAM G bill states "The State Governments shall notify in advance, a period aggregating to sixty days in a financial year, covering the peak agricultural seasons of sowing and harvesting, during which works under this Act, shall not be undertaken." This is in total contrast to what was there in MNREGA. The deletion of Gandhi's name is also a point in the new scheme where name RAM has been introduced through linguistic acrobatics. It is Hindu nationalist ideology, which spread hatred in the society due to which we had to lose the father of our Nation. (as per Sardar Patel). Gandhi is such a global figure now that he cannot be sidelined. So, he has been made the ambassador of Swachh Bharat Abhiyan alone. While in this employment scheme he has been deleted, this is a political signal from BJP that it is not Gandhi whose ideology they pursue.

So this change shows the BJP agenda to quite some extent, away from Gandhi's ideology, undermines federalism, the concept of Rights and doesn't care for the marginalized!

Grand Salami Conference in Memory of Dr. Manmohan Singh Held in Nuh



Nuh, Haryana: A “Dr. Manmohan Singh Grand Salami Conference” was successfully organized yesterday in Nuh to pay tribute to the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. The conference witnessed the presence of several eminent political, social, and intellectual personalities from different regions and communities. Former Member of Parliament Mr. Bijender Singh graced the conference as the Chief Guest. Prominent leaders from Rajasthan, including senior Meena community and marginalized sections’ leader Mr. K.C. Ghumariya, Muslim social thinker Hafiz Manzoor Ali Khan, former Union Minister Chaudhary Virender Singh, along with many other political and social figures, actively participated in the event. The conference was conducted by Mr. Ch. Akbar Qasmi, while the program was organized by the Saanjhi Virasat Manch.

On this occasion, Mr. Sajjad Khan, Founder and CEO of Hijrat International Group, warmly hosted and extended hospitality to all the dignitaries and participants. The event was held in Nuh (Meewat) and was further enriched by an address from Ms. Arifa Utsahi, who joined and spoke from Delhi. Speakers highlighted Dr. Manmohan Singh’s contributions to the nation, his commitment to constitutional values, social harmony, inclusive development, and his lifelong dedication to democratic institutions. The conference concluded with a collective resolve to uphold the ideals of social justice, unity, and shared heritage, which Dr. Manmohan Singh consistently stood for throughout his public life.

NCERT Textbooks Reflect Ideological Distortions: Ruchika Sharma at IHF Webinar

New Delhi : The Indian History Forum organized a webinar titled “Rewriting the Past: Distortions and Ideological Interventions in NCERT History Textbooks” on 22 December 2025. The session featured historian Dr Ruchika Sharma, who critically examined recent changes in NCERT history textbooks and their implications for historical understanding and social cohesion among millions of students across the country.

In her address, Dr Sharma argued that the NCERT syllabus for students aged 12 to 14 reflects a clear ideological bias, particularly in its treatment of medieval Indian history. She noted that Muslim rulers, especially the Sultans and the Mughals, are disproportionately associated with terms such as plunder, loot, and destruction, while comparable actions by non-Muslim rulers receive little attention. Referring to semantic analyses of textbooks from Classes 6 to 8, she said this framing appears to reflect a deliberate narrative



choice.

Dr Sharma also discussed changes in senior secondary textbooks, including the replacement of the term caste with social realities in Classes 11 and 12. She argued that this shift is ahistorical and downplays the structural nature of caste oppression. She further raised concerns about the composition of NCERT committees, pointing to the presence of members with ideological affiliations that could influence curriculum decisions.

Addressing temple destruction, Dr Sharma challenged the tendency to associate this phenomenon exclusively with medieval Muslim rulers. She cited examples from early medieval South India, particularly during the Bhakti period, where temples linked to Jainism and Buddhism were converted or destroyed as part of sectarian consolidation. She emphasized that religious identities in pre-modern India were fluid and that conflicts also existed among non-Muslim traditions. She added that temple destruction was often driven by political and economic motives rather than religion alone.

Dr Sharma also highlighted the misrepresentation of political alliances across religious

lines. She referred to Mughal Rajput collaborations and Malik Ambar’s use of Maratha forces to show that political pragmatism, rather than religion, shaped most conflicts. She questioned portrayals of Chhatrapati Shivaji as a devout Hindu, noting that Hinduism as a unified category is a colonial construct.

She further expressed concern over the inaccurate presentation of genetic studies related to the Aryan migration debate in Class 12 textbooks, warning that such distortions risk encouraging communalized interpretations of history.

Responding to questions on resisting state sponsored distortions, Dr Sharma acknowledged institutional pressures faced by academics but stressed the need for collective scholarly action.

The session concluded with closing remarks by Raaid Azzam, who thanked Dr Ruchika Sharma and the participants. The webinar was hosted by Raaid Azzam on behalf of the Indian History Forum.

यात्री सुविधा हेतु जयपुर मेट्रो फेज़-2 को लेकर मैट्रो प्रशासन एवं एयरपोर्ट प्रशासन के मध्य हुयी समन्वय बैठक

जयपुर : जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (JMRC) द्वारा जयपुर मेट्रो फेज़-1 के क्रियान्वयन को लेकर जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले दिनों एक उच्चस्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में JMRC, DGCA, CISF, BCAS, AAI एवं जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक को सूरजमल, संयुक्त महानिदेशक (नागर विमानन महानिदेशालय) एवं महेश भुराडिया,



निदेशक कंपनी मामलात, जयपुर मेट्रो ने सामूहिक रूप से संबोधित करते हुए

बताया की एयरपोर्ट के टर्मिनल-1, टर्मिनल-2 तथा प्रस्तावित टर्मिनल-3 को मेट्रो के एयरपोर्ट पर प्रस्तावित भूमिगत मैट्रो स्टेशन के साथ निर्बाध रूप से जोड़ने की योजना पर चर्चा की गई है। हवाई अड्डे तक प्रत्यक्ष मेट्रो कनेक्टिविटी से यात्रियों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी तथा शहर में सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

JMRC के निदेशक (कंपनी मामलात) महेश भुराडिया ने कहा

कि सीतापुरा से टोड़ी मोड़ तक, एयरपोर्ट होते हुए प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर जयपुर को विश्वस्तरीय शहरी परिवहन सुविधा प्रदान करेगा।

अनिमेष भट्ट, चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर, जयपुर एयरपोर्ट ने कहा कि मेट्रो अलाइनमेंट, यात्री आवागमन प्रबंधन तथा सुरक्षा मानकों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है, और सभी एजेंसियों ने मिलकर परियोजना को शीघ्र और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

'सुशासन दिवस' के अवसर पर जयपुर मेट्रो में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन

जयपुर : भारत रतन, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर दिनांक 25.12.25 को मानसरोवर मेट्रो डिपो सभागार में 'सुशासन दिवस' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जयपुर मेट्रो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भारत रतन, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी

वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान जयपुर मेट्रो अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने की सुशासन शपथ ली।

जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक श्री वैभव गालरिया ने 'सुशासन दिवस

के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित की और बताया कि इस आयोजन के माध्यम से न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों में जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा की भावना मजबूत होगी, बल्कि आधुनिक तकनीक एवं नवाचारों के माध्यम से राजकीय कार्यों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण संपादन में भी सहायता मिलेगी।



SUBSCRIPTION FORM TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :
Address :

Email:.....
Contact Phone No.....
for donation ☐ /life ☐ /10 yrs ☐ /5 yrs ☐ subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-)
through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I,
Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
or email : timesofpedia@gmail.com

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi
Punjab National Bank, Nanak Pura Branch,
New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700



“First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win.”

- Mahatma Gandhi

ADVERTISEMENT TARIFF TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:

Language: English, Hindi and Urdu

Printing: Front and Back - 4 Colours, Inside pages - B&W

No. of Pages: 12 pages (more in future)

Price: Rs. 3/-

Print order: 25,000

Periodicity: Weekly

Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.

Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page

Please Add Rs. 10 for outstation cheques.

50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA

Send your subscriptions/memberships/donations etc.

(Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi

Punjab National Bank, Nanak Pura Branch, New Delhi-110021

A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

चेहरे पर आएगा कुदरती निखार! रोजाना सुबह पिएं चिया सीड्स का पानी

चिया सीड्स स्किन के लिए एक शक्तिशाली सुपरफूड हैं जो ओमेगा-प फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं। रोजाना चिया सीड वॉटर पीने से स्किन हाइड्रेट रहती है, स्किन हेल्दी और चमकदार बनती है। एक्सपर्ट ने बताया कि क्या चिया सीड्स वॉटर को रोजाना पी सकते हैं।

हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए अक्सर लोग महंगे प्रोडक्ट पर सबसे पहले भरोसा करते हैं, जबकि हमारी रसोई में सुंदरता का असली खजाना छिपा हुआ है। हेल्दी और ग्लोइंग स्किन की चाह में लोग अपने चेहरे पर प्रोडक्ट लगाते हैं, लेकिन उनको उनके मन का रिजल्ट नहीं मिलता है।

रसोई में मौजूद चिया सीड्स स्किन के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं, वजन घटाने वाले लोग चिया सीड्स का सेवन अपनी



डाइट में करते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यह हमारी स्किन के लिए भी उतने ही फायदेमंद होते हैं। सुबह खाली पेट चिया सीड वॉटर पीना न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि स्किन को नेचुरल ग्लो भी देता है।

आयुर्वेद में चिया सीड्स को सेहत और त्वचा दोनों के लिए लाभकारी माना गया है, चिया सीड्स में ओमेगा-प फैटी एसिड, फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट्स और जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसलिए यह ओवरऑल हेल्थ के साथ स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं।

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और

गट कोच डिंपल जांगड़ा के अनुसार, चिया सीड्स में पाए जाने वाले मिनरल्स बॉडी को अंदर से पोषण देते हैं, जिसका सीधा असर हमारी स्किन पर दिखाई देता है। अगर सही मात्रा में लिया जाए तो चिया सीड्स वॉटर रोज पिया जा सकता है। अगर आप रोजाना चिया सीड्स वॉटर रोजाना पीते हैं तो इससे हमारी स्किन को कई सारे फायदे मिलते हैं।

ग्लोइंग स्किन के लिए हाइड्रेशन सबसे जरूरी होता है। चिया सीड्स पानी में डालने पर अपने वजन से ८-१० गुना पानी सोख लेते हैं और जेल जैसा बन जाते हैं। जब आप इसे पीते हैं, तो यह

शरीर और स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है। मौसम बदलने पर जब स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है, तब यह ड्रिंक खास तौर पर फायदेमंद होती है।

चिया सीड्स में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो समय से पहले झुर्रियां और डल स्किन का कारण बनते हैं। ऐसे में जब आप रोज सुबह चिया सीड वॉटर पीते हैं तो स्किन की उम्र बढ़ने की स्पीड स्लो होने लगती है और चेहरा लंबे समय तक फ्रेश दिखता है।

चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-पैटी एसिड स्किन की बाहरी परत को मजबूत बनाता है और इससे नमी लॉक रहती है। इसके अलावा स्किन सॉफ्ट और स्मूद होती है। जिन लोगों को ड्राई स्किन, एक्जिमा या सोरायसिस जैसी दिक्कतें होती हैं, उनको भी आराम मिलता है।

नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए पीएम मोदी ,



दिल्ली : ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर की शादी की रिसेप्शन पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपल को गिफ्ट देते और उनके साथ फोटोशूट कराते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपल को आशीर्वाद दिया है और उनसे बातचीत भी की है।

बता दें कि इसी साल जनवरी में नीरज चोपड़ा ने हिमानी मोर से शादी की थी। उन्होंने तब शादी की किसी को भनक भी नहीं लगने दी थी। परिवार जनों और कुछ करीबी लोगों की उपस्थिति में नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंधे थे, जिसकी तस्वीरें बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया था कि वे हिमानी के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। अब शादी के तकरीबन एक साल बाद नीरज चोपड़ा और हिमानी ने रिसेप्शन का आयोजन किया है। दोनों ने दिसंबर को करनाल में रिसेप्शन दिया था और दिल्ली के द लीला पैलेस में दूसरा रिसेप्शन आयोजित किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में नीरज के रिसेप्शन में कई हस्तियों ने हिस्सा लिया और इसमें

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे।

आपको बता दें कि नीरज और हिमानी ने कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी से उनके घर लोक कल्याणा मार्ग पर मुलाकात की थी।

पीएम मोदी ने दोनों के साथ अपनी फोटो भी शेयर करते हुए एक्स पर लिखा था, 'आज नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से अपने घर लोक कल्याणा मार्ग पर मुलाकात की। हमने कई मुद्दों पर बात की जिनमें खेल भी शामिल रहा।'

नीरज चोपड़ा के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था।

पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप और डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनकी पत्नी हिमानी मोर की बात करें तो हिमानी टेनिस खेलती थीं और उन्होंने न्यूहैम्पशर की फ्रैंकलिन पीयर्स यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री भी की है। उन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस से पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एज्युकेशन की पढ़ाई की है।

वैज्ञानिकों ने बनाया खास हेयर सीरम

ताइपे के वैज्ञानिकों ने एक नया हर्बल हेयर ग्रोथ सीरम बनाया है जो 56 दिनों में बालों की मोटाई और घनत्व में 25 प्रतिशत तक सुधार करता है। इस सीरम में कैन्टेला एशियाटिका, ग्रोथ फैक्टर्स और कैफीन जैसे तत्व शामिल हैं जो बालों के रोम को सक्रिय करते हैं। पुरुष और महिला दोनों के

बालों का झड़ना आज पूरी दुनिया में बड़ी समस्या बन चुका है। इससे बचने के लिए लोग तरह-तरह के शैंपू, कंडीशनर, हेयर मास्क और पता नहीं कौन-कौन से तरीके आजमाते हैं। वहीं टीवी और अखबार में आने वाले विज्ञापन भी लोगों के मन में एक उम्मीद जगा देते हैं।

सर्दियों में रोज नहाना चाहिए या बिना इसके चल जाएगा काम

सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग सुबह-सुबह इस धर्मसंकट में फंस जाते हैं कि आज नहाएं या नहीं। नहाना जरूरी है लेकिन क्या सर्दियों में भी रोज नहाना चाहिए। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि विज्ञान का इस पर क्या मत है। सर्दियों की सुबह हम सभी लोग

एक कशमकश से गुजरते हैं कि आज नहाएं या नहीं। कड़ाके की ठंड में रोज नहाना कोई जंग लड़ने जैसा लगता है। कई बार हम घरवालों के दबाव की वजह से कंपकपाते हुए नहा तो लेते हैं लेकिन विज्ञान और त्वचा विशेषज्ञ इस बारे में कुछ अलग ही राय रखते हैं।

मिल्क, ब्लैक या ग्रीन टी, जानें सेहत के लिए कौन सी चाय है बेहतर?

भारत में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। कई लोग दूध वाली चाय पीते हैं जबकि कई हेल्थ कॉन्शस लोग ब्लैक या ग्री टी भी पीते हैं। ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि रोजाना पीने के लिए मिल्क टी, ब्लैक टी या ग्रीन टी में से कौन-सी ज्यादा बेहतर है और क्यों।

चाय ज्यादातर भारतीयों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। आमतौर पर लोग सुबह चाय पीकर ही अपना दिन शुरू करते हैं और शाम को चाय के साथ अपनी दिन की थकान दूर करते हैं। काम के बीच छोटा सा ब्रेक, थकान



दूर करनी हो या अपनों के साथ बैठकर बातें करनी हो चाय हर मौके पर साथ देती है। कुछ लोगों के लिए दूध वाली चाय के बिना दिन अधूरा लगता है तो कुछ लोग सादी काली चाय या ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं।

जब सेहत की बात आती है तो सवाल सिर्फ पसंद का नहीं रहता, बल्कि यह होता है

कि रोज चाय पीने से शरीर को असल में क्या फायदा मिल रहा है। दूध वाली चाय, ब्लैक टी और ग्रीन टी तीनों एक ही पौधे से बनती हैं, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका और इनमें मिलाई जाने वाली चीजें अलग-अलग होती हैं। आज हम इस खबर में जानेंगे कि रोजाना पीने के लिए कौन सी चाय बेहतर है और क्यों।

मिल्क टी यानी दूध वाली चाय ज्यादातर लोगों की फेवरेट है। दूध से बनी इस चाय को पीने से शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और फैट मिलते हैं। सेहत के लिहाज से यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनको भूख कम लगती है या जिन्हें थोड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। समस्या तब होती है जब इसमें बहुत ज्यादा चीनी डाली जाती है या बार-बार पी जाती है। रोजाना पीने के लिए दूध वाली चाय तब बेहतर हो सकती है जब इसे सीमित मात्रा में पीया जाए और चीनी कम डाली जाए।

کوئی حیرانی سی حیرانی ہے

دیتا ہے جو یاد ہو، خواہ کسی بھی پارٹی سے کھڑا ہو، کئی جگہوں پر یادوں کی اس ذہنیت کی وجہ سے اسے اپنی سیٹ گوانی پڑی ہے، دوسری کمی آرہے ڈی میں یہ رہی کہ وہ اپنا ووٹ دوسرے طبقوں میں بڑھانے میں ناکام رہی، اس کے علاوہ انڈیا اتحاد کی پارٹیوں کے درمیان انتشار تھا، الہی کی مثال اس جیسی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ”وہم جمیعاً وقلوبہم شتی“ سے کیا ہے، وہ سنترے کی طرح یک جٹ دکھائی رہے تھے، لیکن ان کی قاتلین چھلکے کے نیچے الگ الگ تھیں، وہ اپنے کو خربوزہ نہ بنا سکی، جس کی لکیریں اوپر سے علیحدہ دکھائی دیتی ہیں، لیکن اندر سے پورا پھل ایک ہوتا ہے، ایم آئی ایم نے پانچ سیٹوں پر جیت درج کرانی اور کانگریس سے اچھی پوزیشن میں آئی، مگر وہ اپنا دائرہ بڑھانے میں ناکام رہے اور کسی دوسرے علاقے سے انہیں کامیابی نہیں ملی، اپنے منصوبوں سے دوسروں کو کامیاب کرانے والے پرشات کشور صفر پر آؤٹ ہو گئے، البتہ وہ بی بی پی کے جتانے میں معاون ہوئے، کیوں کہ سیاست میں ان کے داخلے سے سیکولر امیدواروں کے ووٹ کیے اور بی بی پی کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ انڈیا اتحاد کے کمیشن سنی جو نائب وزیر اعلیٰ کے چہرہ تھے، ان کی پارٹی بھی جن سوراج کی طرح ہار کر صفر پر آؤٹ ہو گئی، جن لوگوں نے اس انتخاب میں سیکولر پارٹیوں کے لیے کام کیا، وہ ووٹ کے تناسب بڑھانے میں کامیاب رہے، لیکن ووٹوں کو منتشر ہونے سے وہ نہیں بچا سکے۔

تجربہ ہوتا رہے گا، لیکن ابھی تو سب حیرت میں ہیں، خود این ڈی اے کو بھی اتنی بڑی کامیابی کا یقین نہیں تھا، غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جب تک بھلیٹ ووٹوں کی گنتی چلتی رہی، مہا گنڈھنن آکے رہا اور جیسے ہی وی ای ایم کھلا، تڑپ بدل گیا اور وی ایم کی گنتی میں این ڈی اے کو سبقت حاصل رہی، گنتی کے وقت سی سی کرہ کے بند ہونے، مگرانی کی مدت میں کیمبرہ کے فیل ہوجانے اور سڑک کے گرد انتخاب سے متعلق کاغذات بڑی تعداد میں ملنے کا بھی الیکشن مشنر نے نوٹس نہیں لیا، بعض جگہوں پر دوبارہ گنتی کر کر عظیم اتحاد کے امیدواروں کو ہرایا گیا، یہ سارا کچھ ہوا، انتخاب کا عمل بھی پھر مکمل ہو گیا، انتظار رہی حکومت کی تشکیل کا ہے اور اس کا بھی کہ نیشنل کمار دوسری بڑی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہو کر بھی بی بی پی کے دباؤ کے بغیر حکومت کر سکیں گے، بہار کا مستقبل اسی پر موقوف ہے۔

بن کر کیا اور بڑی کامیابی حاصل کی، این ڈی اے میں جیتن رام مانجھی اور اوپندر کشواہا کی پارٹی نے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور چھ سیٹیں ان دونوں پارٹیوں کو ملی تھیں، ان میں ”ہم“ نے پانچ اور آر ایل ام نے چار پرچ کا جھنڈا گاڑ دیا۔

بات انڈیا اتحاد کی کریں تو آر بے ڈی اور کانگریس اس کی اہم پارٹیاں تھیں، کانگریس کا کہنا چاہیے کہ صفایا ہو گیا، اکسٹھ سیٹوں میں صرف پانچ سیٹ، وہ بھی آل انڈیا پارٹی کے لیے، بڑی شرم کی بات ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کانگریس کے پاس بہار میں تقریباً دو دہائیوں سے قیادت تھیں، تنظیمی ڈھانچہ ٹوٹ چھوٹ کر ختم ہو گیا ہے، پارٹی کے صدر اور ذمہ دار مرکز سے ملے ہوتے ہیں، اس لیے کارکنوں میں کوئی امنگ نہیں ہے، وہ سرد مہری کے شکار ہیں، انتخابی ذمہ داری جنوبی ہندوستان کے کسی لیڈر کے حوالہ کردی جاتی ہے، اس بار بھی ”الگو“ تھے، پورا ہندوستان اس بات کو جانتا ہے کہ شمال و جنوب میں سیاست کا الگ الگ انداز ہے، اس لیے جنوب سے آئے مشاہد اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ نہیں کر سکتے، صحیح حکمت عملی تیار نہیں کر پاتے، اس لیے کانگریس ختم ہوتی جا رہی ہے، جمہوریت کی لڑائی لڑنے والے کی پارٹی میں ہی جمہوریت کا فقدان ہے، کھڑے پارٹی کے صدر ضرور ہیں، لیکن وہ بھی رائل گاندھی کی پسند ہیں اور رائل گاندھی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ استے دن سیاست میں رہنے کے بعد یہی طے نہیں کر پاتے ہیں کہ انہیں نہرو والی سیاست کرنی ہے یا رام منو ہر لیا والی، وہ ان دونوں سیاسی نظریوں میں تفریق نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے ان کی سیاست کے اثرات ووٹ میں تبدیل نہیں ہو پاتے۔

انڈیا اتحاد کی بڑی پارٹی آر بے ڈی ہے، رائے دھندگان میں ان کے MY تسی کرن کا چرچا بہت رہتا ہے، مائی M مسلمان اور Y یادوں سے عبارت ہے، واقعہ یہ ہے کہ مسلمان آر بے ڈی کو ایمانداری سے ووٹ دیتا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسے سیکولر سمجھتا ہے اور اس لیے بھی کہ اس کے پاس دوسرا متبادل بھی نہیں ہے، تیسویں جوان ہیں، ان کے پاس توانائی ہے، کام کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن مواقع انہیں نہیں ملتے، اس پر سب بدعنوانی کا الزام، لالو جی کی جیل یاترا، خاندانی جھگڑے، دو بھائیوں کا انتخاب میں دست و گریباں ہونا اور ایک دوسرے کو ہرانے کی جدوجہد یہ سب بھی رائے دھندگان پر اثر انداز ہوتے ہیں، دوسری بڑی خرابی MY کے Y میں یہ ہے کہ وہ پارٹی امیدوار کے بجائے اس کو ووٹ

کے کارکنوں نے بوتھ دائرہ پر چار کیا اور ہر ہر بوتھ پر اپنے آدمی کھڑے کیے، بی بی پی نے نیشنل مارکی قیادت میں انتخاب لڑا اور اس کو مکھڑا بنا کر پرچار میں لگے رہے، اس کا فائدہ بی بی پی کو ملا اور وہ بہار میں اول نمبر پر آگئی اور بے ڈی کو بچھڑ چھوڑ دیا، بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آنے کے بعد اب یہ بحث زوروں پر چلنے لگی ہے کہ این ڈی اے نیشنل مارکوبی وزیر اعلیٰ بنائے گی یا کوئی نیا وزیر اعلیٰ بی بی پی سے ہوگا، نیشنل مارک اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات آئی اور وہ عظیم اتحاد کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوئے تو ان کو پہلی مارنے میں دیر نہیں لگے گی، وہ نو (9) پارسی میں اقلیت میں رہ کر وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ایک بار اور سوچ، پہلے آر بے ڈی ان کو اپنے ساتھ لینے سے انکار کر چکا ہے، کیوں کہ عظیم اتحاد نے تجویز کو وزیر اعلیٰ کا چہرہ بنا کر پیش کیا تھا، اب جبکہ آر بے ڈی کا یہ خواب ملایمٹ ہو چکی ہے، تو تجویز پھر سے نائب وزیر اعلیٰ ہونے کو تیار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب امکانات ہیں، اگر بی بی پی نے بہار میں وزیر اعلیٰ بدلنے کی کوشش نہیں کی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، کینڈ بی بی پی کے پالے میں ہے، اس کے جوڑ توڑ کی صلاحیت نیشنل مارک سے زیادہ ہے، عارف محمد خاں کو بہار میں اسی لیے لاکھ رکھا گیا ہے، ہر مہرہ اپنی جگہ فٹ ہے، بی بی پی جیسا چاہے گی وہی ہوگا، ایسے میں مودی جی کو ایک خطرہ مرکزی حکومت کے گرنے کا بھی ہوگا، جو نیشنل اور چندرا بابو نائیڈل کی بیساکھی پر قائم ہے۔

این ڈی اے کی تیسری حلیف پارٹی لوجپا (آر) ہے، چراغ پاسوان کی سربراہی میں اس کی کارکردگی پارلیامنٹ اور اسمبلی دونوں میں اچھی رہی ہے، بہار اسمبلی میں بھی اس کی کامیابی کا تناسب اچھا رہا ہے، اس کی اہمیت بھی مسلم ہے، کیوں کہ دولت نیتا اصلاً وہی ہیں، جیتن رام مانجھی اور دوسروں بلکہ ان کے بچپا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، 2020 کے چناؤ میں آر بے ڈی کو کامیابی ملی تھی، اس کی ایک بڑی وجہ چراغ پاسوان کا این ڈی اے سے الگ ہو کر انتخاب لڑنا تھا، اس بار دولت ووٹ اس لیے بٹ نہیں سکے اور وہ تھوٹ میں این ڈی اے کو گئے، جس نے اسمبلی میں جیت کے اعداد و شمار کو بدلنے میں حیران کن کردار ادا کیا، چراغ پاسوان بخوبی جانتے تھے کہ جب تک بی بی پی اور بے ڈی یو کا کیڈر ووٹ ہمیں نہیں ملے گا، ہم اپنی ذات کے چھوٹی صد ووٹ سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لئے انہوں نے مودی کی ٹھگتی ہونامان

مفتی محمد ثنا، الہدی قاسمی

ووٹ چوری، ایس آئی آر میں ہیرا پھیری، ووٹنگ سے قبل ریوڑی کی تقسیم جیسے الزامات کے ساتھ بہار انتخاب میں این ڈی اے نے فتح کا حیران کن پرچم بلند کیا ہے اور اس نے دوسو سے زیادہ سیٹوں پر جیت درج کر کے بہار میں اپنے ہی 2010 کے رکارڈ کو توڑ دیا ہے، تجسوسی کے بڑے بڑے انتخابی وعدے اور رائل گاندھی کے مسلسل دوروں نے عوام پر اثر نہیں چھوڑا، آر بے ڈی کے خواب تو چٹنا چور ہوئے ہی، کانگریس بھی تاریخ کے بدترین دور سے گزری، ملاح کے بیٹے مکیش سبھی کا کھانا نہیں کھل سکا، بائیں بازو کی پارٹیوں کی کارکردگی بھی اچھی نہیں رہی، بہار کی عوام نے بتا دیا کہ بعض نعرے خوش کن ہوتے ہیں، لیکن ان میں رائے دھندگان کے ووٹوں کو بدلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیوں کہ رائے دھندگان اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کا نفاذ عملاً ممکن نہیں ہے، جیسے ہر خاندان کے ایک فرد کو سرکاری نوکری وغیرہ

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عوام نے بے ڈی یو کو ووٹ دے دے، وہ نیشنل مارکی بہترین کارکردگی کے عوض دیا، نیشنل مارک تمام انتخابی تقریروں میں اپنے کام گناتے رہے، دوسری پارٹیوں کے بخیہ ادھیڑنے پر ان کی توجہ کم رہی، وقف ایکٹ 2025 کی حمایت، مدارس ملحقہ کے معاملات و وسائل سے ان دیکھی، بہار اردو اکاڈمی کا آٹھ سالہ تعطل کوئی بھی معاملہ ان کے ووٹ کو متاثر اس لیے نہیں کر سکا کہ رائے دھندگان نے ان مسائل کو مسلمانوں کے مسائل کے طور پر دیکھا، اسے ریاست کی ضرورت نہیں سمجھا، بلکہ ان معاملات کی وجہ سے وہ لام بند اور پولورائز ہوئے اور ووٹ نیشنل مارکی جھولی میں چلا گیا، اس کا پورا پورا فائدہ بے ڈی یو کو مل گیا، اس کے علاوہ شراب بندی اور ایک کروڑ ترین لاکھ خواتین کو دس دس ہزار رقم کی فراہمی نے بھی خواتین کے ووٹ کو نیشنل مارک کے لئے متھ کر دیا، وہ لڑکیاں بھی نئے ووٹروں میں تیش کمار کے لیے کام کرتی رہیں، جنہوں نے اسکو لیٹیم نیشنل مارک کے سائیکل یوجنا سے لی سائیکل چڑھ کر پاس کیا تھا، بجلی کے نظام کی بہتری اور سڑک کی عمدگی نے بھی نیشنل مارک کو ووٹ دلا وہی لیا۔

این ڈی اے کی مضبوط اور تنظیمی اعتبار سے طاقت ور پارٹی بی بی پی نے لالو یادو کے دور حکومت کو جنگل راج اور ان کے خاندان کے بدعنوان ہونے کی بات بار بار اٹھائی، آریس ایس

اعلامیہ برائے ”چوتھا سالانہ مشاورتی اجلاس، مرکز تحفظ اسلام ہند“

اعلان کرتا ہے کہ مدارس کا تحفظ صرف علماء کا نہیں بلکہ پوری امت کا فریضہ ہے۔ مدارس کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں، میڈیا پر ویڈیوز، اور ان کی شبیہ کو مجروح کرنے کی منظم کوششیں دراصل امت کے فکری اور روحانی مرکز پر حملہ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام اور نوجوان نسل کو واضح طور پر بتایا جائے کہ مدارس شدت پسندی کی علامت نہیں، بلکہ قرآن، اخلاق، خدمت اور انسانیت کی تعلیم کے مراکز ہیں۔ یہ ادارے ہمیشہ ملک کی آزادی، اس کے امن و اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کے محافظ رہے ہیں۔ اس لیے ملت اسلامیہ کو باخبر رہنا ہوگا کہ مدارس کے خلاف کسی بھی سطح کی سازش، بکل کے دین اور آنے والی نسل کے ایمان کے خلاف منصوبہ ہے۔ مرکز تحفظ اسلام ہند پوری شدت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ مدارس کی آزادی، ان کے نظام کی حرمت، اور ان کی دینی شناخت پر کسی بھی قسم کی دست درازی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کے دفاع، وضاحت اور تحفظ کے لیے ہر پلیٹ فارم اور ہر سطح پر قانونی، اخلاقی اور اجتماعی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔

تحفظ اوقاف:

اوقاف امت مسلمہ کی امانت اور تاریخی ورثہ ہیں۔ افسوس کہ آج ملک کے مختلف حصوں میں اوقاف کی زمینوں پر قبضہ، سرکاری مداخلت، اور تزامیم کے ذریعے اس نظام کو کمزور کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔

قانونی، فکری، علمی اور عوامی محاذوں پر ہر ممکن جدوجہد کی جائے گی، تاکہ امت کے ایمان، فکر اور احساس محبت رسولؐ کو ہر سازش اور باطل نظریہ سے محفوظ رکھا جاسکے۔

دفاع صحابہ کرامؓ و اہل بیت اطہارؓ:

مرکز تحفظ اسلام ہند کا یہ اجلاس اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اسلام کے اصل ستون ہیں۔ انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے قرآن و سنت ہم تک پہنچا۔ لہذا ان کی شان میں گستاخی دراصل اسلام کی جڑ پر حملہ ہے۔ مرکز تحفظ اسلام ہند اعلان کرتا ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں صحابہؓ و اہل بیتؓ کی تنقیص، تحریف یا بدگویی کو برداشت نہیں کرے گا۔ علماء و خطباء کو چاہیے کہ وہ منبر و محراب سے امت کے دلوں میں صحابہؓ و اہل بیتؓ کی محبت اور احترام کو راسخ کریں، تاکہ نسل نو ایمان و محبت کی اصل بنیاد پر قائم رہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ امت کی روحانی بقا اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے اسلاف سے محبت اور وفاداری کو اپنی شناخت سمجھے، اور اسی نسبت سے اپنی فکری تعمیر کرے۔

تحفظ مدارس اسلامیہ: مدارس اسلامیہ وہ چراغ ہیں جنہوں نے صدیوں تک ہندوستان کے دینی و تہذیبی وجود کو روشن رکھا اور یہ دین کے مضبوط قلعے ہیں۔ آج جب ان کے خلاف مختلف سطحوں پر دباؤ، تحقیقات، پابندیاں اور اصلاح کے نام پر مداخلتیں بڑھ رہی ہیں، تو مرکز تحفظ اسلام ہند

صاحب ایمان کا کردار اور قربانی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ شریعت کے ہر حکم کے نفاذ اور احترام کے لیے علمی و عملی محاذ پر سرگرم رہیں گے۔

تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت ﷺ:

ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ رسول اکرم ﷺ آخری نبی اور شریعت محمدیؐ کے لیے کامل و محفوظ ہے۔ اس اجلاس کے ذریعہ مرکز تحفظ اسلام ہند پوری امت کو خبردار کرتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ، گستاخانہ رسولؐ کی ناپاک سازشیں اور دینی حدود کے خلاف آوازیں، ایمان کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ مرکز اعلان کرتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ملک گیر سطح پر علمی، بیداری اور دعوتی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ امت کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کو حدود و شرع کے اندر رکھتے ہوئے متحہ ہو کر نبی کریم ﷺ کی حرمت کے دفاع میں کھڑی رہے، کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا اور کامیابی کا راستہ ہے۔ مرکز یہ بھی عہد کرتا ہے کہ نبی اکرمؐ کی سیرت طیبہ کو ملکی، فکری اور عصری اسلوب میں بھی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ محبت رسولؐ کے چراغ ہر دل میں روشن رہیں اور امت اپنی اصل نسبت کو نہ بھولے۔ مزید یہ کہ مرکز ختم نبوت کے جھوٹے اور گمراہ کن دعوے داروں، ان کے فتنوں اور پروپیگنڈوں کا پوری قوت، بصیرت اور شرعی حکمت کے ساتھ تعاقب جاری رکھے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے

موجودہ ملکی حالات، نوجوان نسل کو درپیش فکری چیلنجز، دینی شعائر پر حملوں اور امت کے اجتماعی مسائل کے پس منظر میں طویل غور و فکر، مشاورت اور ذمہ دارانہ بحث کے بعد ملت اسلامیہ ہند یہ نام یہ ”دس نکاتی اعلامیہ“ پیش کیا گیا ہے، تاکہ حالات کے اس نازک دور میں ملت کو صحیح سمت، مضبوط لائحہ عمل اور فکری رہنمائی فراہم کی جاسکے۔ ذیل میں اعلامیہ کے یہ اہم نکات پیش خدمت ہیں:

تحفظ دین و شریعت:

مرکز تحفظ اسلام ہند کا یہ اجلاس بحمد اللہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر قائم ہے، اور یہی امت کی بقا، فلاح اور نجات کی ضمانت ہے۔ موجودہ دور میں جب مختلف افکار اور نظریات کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو کمزور کرنے، شریعت کے قوانین کو بدلنے، اور مسلمانوں کے مذہبی تشخص کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مرکز تحفظ اسلام ہند اعلان کرتا ہے کہ دین اسلام کے اصول و احکام پر کسی صورت میں سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مرکز بالعموم پوری ملت اسلامیہ اور بالخصوص اپنے تمام کارکنان، علماء، نوجوانوں اور عوام کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اور اپنی نسلوں کو شریعت کی محبت، قرآن سے وابستگی اور سنت رسولؐ کی پیروی کا درس دیں۔ دین اور شریعت کا تحفظ صرف نعرہ نہیں بلکہ ایک مسلسل جہد عمل ہے، جس میں ہر

مرکز تحفظ اسلام ہند، جس کی بنیاد ۱۰ محرم الحرام ۱۴۴۰ھ مطابق 21 ستمبر 2018ء کو اخلاص، دردمندی اور امت کے فکری و ایمانی تحفظ کے مقدس مقصد کے ساتھ رکھی گئی تھی، آج ایک منظم فکری و تحریکی ادارے کی حیثیت سے ملک کے طول و عرض میں اپنی نمایاں دینی و سماجی خدمات پیش کر رہا ہے۔ اکابر بدین کی علمی و فکری روایت کا امین یہ مرکز جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے نوجوان نسل کے ایمان، فکر، تشخص اور تہذیبی بقا کی حفاظت کے لیے شب و روز سرگرم عمل ہے۔ ملک کے سکتے ہوئے مسائل کے تناظر میں مرکز کی آن لائن و آف لائن کانفرنسیں، فکری نشستیں، تربیتی پروگرام، علمی دروس اور بیداری مہمات ایک مضبوط دعوتی تحریک کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ مرکز کی یہ ترقی و استقامت بالخصوص حضرات اکابر سرپرستان: خادم القرآن حضرت مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی، شیخ طریقت حضرت مولانا محمد عمر بن محفوظ رحمانی اور مقرر ذیشان حضرت مفتی ڈاکٹر محمد مقصود عمران رشادی صاحبان کی رہنمائی، دعا اور شفقتوں کا ثمرہ ہے، جن کی سرپرستی نے سفر کو سمت، استحکام اور برکت عطا کی۔ اسی فکری و تحریکی تسلسل کے ساتھ مرکز تحفظ اسلام ہند کا چوتھا سالانہ مشاورتی اجلاس مورخہ 07-08 نومبر 2025ء بروز منگل و اتوار، بمقام جامعہ تعلیم القرآن، راگہ بلی، بنگلور میں منعقد ہوا، جس میں ملک کے مختلف صوبوں سے تشریف لائے اراکین مرکز نے شرکت فرمائی۔

Dialogue, Power and Prudence: Rethinking Muslim Engagement with RSS and the Indian State



Najmuddin Farooqi

The question of whether Indian Muslims should engage in dialogue with Mohan Bhagwat, the RSS Chief or directly with the BJP-led government raises an even more fundamental question: why engage at all and with whom?

Several explanations are often offered. First, there is genuine anxiety within the community about the present political and social climate. Second, some perceive Mohan Bhagwat as a comparatively moderate voice within the Hindutva ecosystem. Third, it is believed that engaging with a single individual who symbolically represents and arguably shapes the ideological core of Hindutva may be more practical than navigating multiple layers of government.

Whatever the motivation, not every attempt at dialogue should be viewed as a conspiracy or a betrayal. Assigning blame, questioning intentions or purpose of Muslim NGOs individual or group is futile and unnecessary. A crucial question must be addressed upfront: What are the expected



outcomes of such dialogue and at what cost?

Before delving into tactical advantages or disadvantages, Indian Muslims should seek clear answers to certain fundamental and principled questions from Mohan Bhagwat himself: "How does he view Hindu minorities living in Muslim-majority countries such as Pakistan, Bangladesh, or Arab nations? Does he advise the Sanatan Hindu to cross religious boundaries to demonstrate loyalty to their nations? Should they publicly denounce India as an enemy country to prove their own patriotism? Is it ethical for a religious majority or state system to dictate to a minority what aspects of their faith are acceptable and what not? And finally, is it justifiable to engage with just any individual to deliberate on the jurisprudence of another religious faith, rather than consulting its recognised

clergy those who are widely acknowledged and respected, even beyond international borders, within the religious community to which they belong in order to arrive at a fair, informed and credible conclusion?"

These questions are not rhetorical, they go to the heart of reciprocity, ethics and minority rights. Without clarity on these issues, dialogue risks becoming symbolic rather than substantive.

Engagement also carries potential casualties. One must assess Bhagwat's actual influence both within the RSS cadre and within the ruling establishment. Is his leadership strong enough to reshape attitudes on the ground? Has the RSS genuinely transformed its ideological legacy, spanning from M.S. Golwalkar to the present, or does historical baggage continue to shape its worldview? Can the painful and

controversial actions and the legacy of RSS which continues to exist throughout hundred years history realistically and logically be erased from our collective memory?

Can the Indian Muslims, through dialogue, meaningfully alter the deeply entrenched perceptions held by large sections of the Hindu majority? Dialogue alone cannot undo decades of mistrust unless it is accompanied by institutional change and consistent action.

Given these complexities, it is essential to reconsider the broader political reality. Ignoring the undeniable influence of Prime Minister Narendra Modi on the Hindu psyche would be unrealistic. His government's command over governance structures, media narratives and its perceived influence over constitutional institutions is a defining feature of contemporary India.

This raises a critical counter-question: if engagement is necessary, why not engage directly with the government of the day, which holds executive power enforcement of law and order deployment of security forces and shapes policy outcomes?

In conclusion, dialogue is not inherently wrong but it must be strategic, principled and grounded in realism. Indian Muslims must carefully weigh intentions, power structures, historical context and tangible outcomes before choosing whom to engage with and on what terms. Dialogue should be a means to justice and equality, not an end in itself.

Finally, no matter what challenges come our way, we must never lose faith in ourselves. Success will inevitably be achieved sooner or later and it can be attained without compromising our rightful faith and beliefs.

لائسنسنگ کو آسان بنانے سے صنعتوں کو راحت ملی ہے: ریکھا گپتا

کیا گیا ہے۔ پہلے سال میں ہزاروں کروڑ کی منظوری دی گئی۔ صنعت کے وزیر منجندر سنگھ سرسانے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ اس تاریخی صنعتی علاقے نے 100 سال کا کامیاب سفر مکمل کیا ہے۔ سرسانے کہا کہ اپنے دور اقتدار کے پہلے سال میں وزیر اعلیٰ نے صنعتی علاقوں میں سڑکوں، طوفانی پانی کی نکاسی اور اسٹریٹ لائٹس کے لیے 1000 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پہلا ٹریڈرز ویلفیئر بورڈ بنانے کا بھی اعلان کیا جس کے ذریعے صنعت و تجارت اپنے مسائل اور تجاویز براہ راست حکومت تک پہنچا سکیں گے۔



بتایا کہ انڈسٹری سے متعلق لائسنسنگ کے طریقہ کار کو آسان بنایا گیا ہے۔ تمام قسم کی اجازتوں کو سنگل ونڈوسٹم کے ذریعے ہموار ہے۔ اتوار کو وزیر اعلیٰ نے فرینڈز کالونی انڈسٹریل ایریا کی صد سالہ تقریبات میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران، انہوں نے

نئی دہلی (ایجنسیاں) وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ حکومت صنعتی مفادات کو ذہن میں رکھ کر فیصلے کر رہی ہے۔ اس کا مقصد صنعت کو نئی تحریک دینا اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنا ہے۔ حکومت نے گزشتہ 10 مہینوں میں انڈسٹری سے متعلق کئی اہم فیصلوں پر عمل درآمد کیا ہے، جن میں لائسنسنگ کے طریقہ کار کو آسان بنانا اور سنگل ونڈوسٹم شامل ہے۔ تمام قسم کی اجازتوں کو اب آسان کر دیا گیا ہے۔ سی ایم گپتا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کاروبار کرنے میں آسانی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مسلسل عملی اور صنعت دوست فیصلے کر رہی

دہلی نے اس سال سائبر فراڈ سے گنوا دئے 1200 کروڑ

زیادہ دھوکہ بازوں کو پکڑا ہے۔ پولیس کے مطابق، 2024 میں، دہلی میں متاثرین کو مجموعی طور پر تقریباً 100,1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، جس میں سے تقریباً 10 فیصد بینک کھاتوں میں منجمد کر دیے گئے۔ اس سال، دہلی پولیس، بینکوں کے ساتھ مل کر، تقریباً 24 فیصد فراڈ شدہ رقوم کی وصولی میں کامیاب ہوئی ہے۔ اگر آپ دھوکہ دہی کا شکار ہیں تو ان چار مراحل پر خصوصی توجہ دیں۔ اگر آپ سائبر گھونالے کا شکار ہو جاتے ہیں تو 1930 پر کال کریں یا cybercrime.gov.in پورٹل پر شکایت کریں۔ لیکن اس سے پہلے چار قدم ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے، متاثرہ کو فوری طور پر کافذ کے کٹکے پر اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر کھانا چاہیے۔

IFSO کا دعویٰ ہے کہ عوام میں بیداری میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اب بھی نئے طریقہ کار کا شکار ہوتے ہیں۔ ان ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دہی سال کے دوران، ڈیجیٹل گرفتاریوں، سرپاہ کاری اور تجارتی ایپ گھونالوں، مینی ٹریڈز، فیکٹ، کریپٹو لائڈرنگ، اور کال سینٹر لون اسکیم جیسے واقعات نے متعدد لوگوں کو نشانہ بنایا۔ سائبر کرائم میں خچر بینک اکاؤنٹس اور خچر موبائل سم کارڈ استعمال کیے گئے۔ فراڈ شدہ فنڈز کے انعقاد میں بہتر پالیسیاں سال تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سب سے زیادہ سائبر فراڈ خچر اکاؤنٹس کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ دہلی پولیس نے اپنے سائی ہاک آپریشن میں بڑی تعداد میں دھوکہ بازوں کو پکڑا ہے، جس نے اب تک 000,1 سے

اسٹریجٹ آپریشنز کے ہیں۔ دہلی بھر میں 12 ارب روپے کی فراڈ کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ IFSO نے اس سال تقریباً 24 فیصد دھوکہ دہی کی رقم پکڑی ہے، جو پچھلے سال پکڑی گئی رقم سے 14 فیصد زیادہ ہے۔ ڈی سی پی کے مطابق، 12 بلین کی دھوکہ دہی پوری دہلی کی آبادی کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں IFSO کے ساتھ درج مقدمات کے ساتھ ساتھ دہلی کے تمام اضلاع کے سائبر پولیس اسٹیشنوں میں درج ایف آئی آر بھی شامل ہیں۔ مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ IFSO کے مطابق، 2025 میں سائبر کرائم کے رجحانات کی فہرست میں اسٹاک انویسٹمنٹ فراڈ سرفہرست رہا۔ ڈیجیٹل گرفتاریاں دوسرے نمبر پر تھیں۔ اس کے علاوہ دیگر مختلف طریقوں سے فراڈ ہوا۔

نئی دہلی (ایجنسیاں) موبائل فون کی گھنٹی، اسکرین پر چمکتا ہوا الٹک، یا منٹوں میں امیر بننے کا وعدہ... بس اتنا ہی، اور کسی بھی وقت میں، دہلی کے باشندے 2025 میں اب تک 200,1 کروڑ سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں۔ سائبر جرائم پیشہ افراد نے خوف، لالچ اور اعتماد کا فائدہ اٹھا کر دارالحکومت میں ایک ہی سال میں سب سے بڑی "ڈیجیٹل ڈکیتی" کا ارتکاب کیا ہے۔ دہلی پولیس حیران ہے۔ یہاں تک کہ دہلی پولیس بھی اتنی رقم سے حیران ہے۔ متعدد سائبر سیکوریٹی مہمات اور بیداری پروگراموں کے باوجود، سائبر کرائمیں دہلی کے باشندوں کو 2025 میں 12 بلین سے زیادہ کا دھوکہ دینے میں کامیاب ہوئے۔ دھوکہ دہی کے یہ اعداد و شمار دہلی پولیس کے انٹیلی جنس فیوژن اور

آٹھواں تنخواہ کمیشن یکم جنوری سے نافذ العمل ہے

نظر ثانی توقع سے جلد آسکتی ہے۔ انہوں نے منٹ کو بتایا کہ حکومت بقایا جات کے حساب کے پیچیدہ عمل کے بارے میں خدشات کو دور کرنے کے لیے معمول سے پہلے اس نظر ثانی کا اعلان کر سکتی ہے۔ ملازمین بھی پچھلی بار کی طرح تاخیر سے بچنے کے لیے بروقت رابطے کی امید کر رہے ہیں۔ پچھلے ایچ آر اے اور آئی اے میں اضافہ اور بقایا جات وقت پر ادا نہیں کیے گئے۔ لہذا، 8 ویں سی پی سی کے تحت نمایاں اضافے کی توقعات زیادہ ہیں۔ بے کمیشن سرکاری ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہوں، الائنسز اور پنشن کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ حکومت کو تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں سفارشات پیش کرتا ہے۔ آٹھواں تنخواہ کمیشن فی الحال اپنی سفارشات تیار کر رہا ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ ان سفارشات کو حکومت کی جانب سے موصول ہونے اور کابینہ سے منظوری کے بعد ہی نافذ کیا جائے گا۔ تب تک ملازمین کو انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن، اچھی خبر یہ ہے کہ اگر تنخواہوں میں اضافہ یکم جنوری 2026 سے لاگو ہوتا ہے، تو اس تاریخ سے اعلان ہونے تک بڑھی ہوئی تنخواہ بقایا جات کی صورت میں دی جائے گی۔



سالانہ کی مجموعی تنخواہ تک بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سرکاری شعبے کے ملازمین کی تنخواہوں میں یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں حالیہ رجحانات کے مطابق ہے اور پچھلے پے کمیشنوں کے فائنل عوام کے مطابق ہے۔ تنخواہوں میں اضافے کا نفاذ کب ہوگا؟ 8 ویں پے کمیشن کی تنخواہوں میں اضافے کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنٹرل پے کمیشن (CPC) نے ابھی تک اپنی سفارشات کا اعلان نہیں کیا ہے اور نہ ہی انہیں نظر ثانی کے لیے حکومت کو بھیج دیا ہے۔ پروفیسر کلیر کے مطابق، یہ

ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یکم جنوری سے آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تاہم، مرکزی حکومت کے قوانین کے مطابق، جب نیا پے کمیشن لاگو ہوگا، ملازمین اور پنشنرز کے بقایا جات یکم جنوری 2026 سے جمع ہوتے رہیں گے، جب تک کہ 8 ویں پے کمیشن کی تنخواہ میں اضافہ کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ ماہر اقتصادیات اور مونی لال نہرو کا کہنا ہے یونیورسٹی کے پروفیسر، رجنیش کلر کا کہنا ہے کہ حکومت کم از کم تنخواہ 000,18 سے بڑھا کر 000,50 فی ماہ اور سب سے زیادہ تنخواہ والے گریڈ کو تقریباً 1 کروڑ

نئی دہلی (ایجنسیاں) وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے 8 ویں تنخواہ کمیشن کی منظوری دے دی ہے۔ مرکزی حکومت کے لاکھوں ملازمین اور پنشنرز تنخواہوں میں اضافے کے منتظر ہیں۔ 8 ویں پے کمیشن کے ارکان کے ناموں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ جسٹس (ریٹائرڈ) رجنیا پرکاش دیبائی چیئر پرسن ہوں گی۔ جج جین، جو 1990 سے آئی اے ایس افسر ہیں، کو ممبر سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ آئی آئی ایم بنگلور کے پروفیسر پلک گھوش کو پارٹ ٹائم ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم، 8 ویں پے کمیشن کے ارکان کے اعلان کے باوجود، ملازمین کو فوری تنخواہ میں اضافہ نہیں ملے گا۔ عام طور پر پے کمیشن کی سفارشات ہر دس سال بعد لاگو کی جاتی ہیں۔ اس کے مطابق، 8 ویں مرکزی تنخواہ کمیشن کی سفارشات 1 جنوری 2026 سے لاگو ہونے کی توقع ہے۔ اکتوبر میں جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن میں، کابینہ نے کہا کہ 8 ویں مرکزی تنخواہ کمیشن کی سفارشات یکم جنوری 2026 سے لاگو ہوں گی۔ کمیشن کی سفارشات ابھی تک موصول نہیں ہوئیں۔ 8 ویں پے کمیشن کی سفارشات ابھی تک موصول نہیں ہوئی

سندھپ ڈکشت کو کانگریس پارٹی میں نئی ذمہ داری سونپی گئی ہے

نئی دہلی (ایجنسیاں) کانگریس تنظیم کے اندر ایک اہم تنظیمی تبدیلی میں پارٹی قیادت نے سینئر لیڈر سندھپ ڈکشت کو تعمیری کانگریس کا صدر مقرر کیا ہے۔ یہ تقرری فوری طور پر موثر ہے۔ تعمیری کانگریس، جسے پہلے آؤٹ ریچ بیل کے نام سے جانا جاتا تھا، اب ایک نئے فارمیٹ اور وسیع کردار کے ساتھ بڑھا چکا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جاری کردہ بیان پر اسے آئی سی سی جرنل سکریٹری کے سی ویو کو پال کے دستخط ہیں۔ کانگریس صدر نے پارٹی کی نظریاتی اور پالیسی کی مضبوطی کو مزید مضبوط کرنے کے مقصد سے یہ تقرری کی ہے۔ سندھپ ڈکشت کی ذمہ داریاں ہوں گی؟ تعمیری کانگریس کو ایک سرشار پلیٹ فارم کے طور پر متعارف کرائے گا جو سوسائٹی کے گروپوں، موضوع کے ماہرین، ماہرین تعلیم، سماجی کارکنوں اور مسائل پر مبنی تنظیموں کے ساتھ براہ راست مکالمہ قائم کرے گا۔ اس کا بنیادی مقصد مختلف سماجی، اقتصادی اور پالیسی موضوعات پر باہمی بات چیت کو فروغ دینا ہے تاکہ زمین حقائق اور متنوع نقطہ نظر کو پارٹی کی پالیسیوں میں شامل کیا جاسکے۔ اس اقدام سے مفاد عامہ کے مسائل پر ٹھوس پالیسیاں بنانے میں مدد ملے گی۔ کانگریس کا خیال ہے کہ اس اقدام سے پارٹی کو سماج کے متنوع طبقوں سے جڑنے، نئے خیالات کو سمجھنے اور مفاد عامہ کے مسائل پر ٹھوس پالیسیاں بنانے میں مدد ملے گی۔ تعمیری کانگریس کے ذریعے پارٹی قیادت کو زمینی تجربے اور ماہرین کی رائے تک براہ راست رسائی حاصل ہوگی۔ سندھپ ڈکشت کا کردار اہم سمجھا جاتا ہے۔ نئے صدر کے طور پر سندھپ ڈکشت کا کردار اہم سمجھا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ ان کے تجربے اور سیاسی سمجھ بوجھ سے تعمیری کانگریس کو ایک نئی سمت ملے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ پلیٹ فارم مستقبل میں کانگریس کی نظریاتی حکمت عملی اور سماجی مکالمے کی مضبوط بنیاد بنے گا۔

تلنگانہ نلہ ملا جنگلات میں خفیہ

خزانے کیلئے کھدائی، کئی افراد زیر حراست

حیدرآباد، (ایجنسیاں) تلنگانہ کے ضلع ناگرکرنول کے کولہا پور فاریسٹ ریج کے تحت نلہ ملا کے گھنے جنگلاتی علاقہ میں خفیہ خزانہ کی تلاش میں غیر قانونی کھدائی کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب ملا چنٹلا پلی بیٹ کے علاقہ میدر بنڈا کے قریب واقع دیوئی پونا نامی مقام پر یہ کارروائی انجام دی جارہی تھی۔ تفصیلات کے مطابق بعض شریپندھن صراں قدیم مقام پر خزانہ کی تلاش میں کھدائی کر رہے تھے کہ اسی دوران محکمہ جنگلات کے حکام نے چھاپہ مار کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حکام نے ملزمین کو حراست میں لے کر کولہا پور فاریسٹ ڈیوٹنٹل کر دیا۔ کارروائی کے دوران کھدائی کے لئے استعمال ہونے والا سامان اور ملزمین کی موٹر سائیکل بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ مقامی دیہاتیوں کا الزام ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے اس غار نامی مقام پر خزانہ کے لئے کھدائی کی جا رہی تھی اور بعض افراد نے وہاں موجود قدیم متون اور فن پاروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ عوامی حلقوں میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کئی مہینوں سے جاری ان سرگرمیوں کا محکمہ جنگلات کو علم کیوں نہیں ہو سکا۔ پکڑے گئے افراد کو مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے اچم پیٹ فاریسٹ ڈویژنل آفس منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام اس بات کی بھی جانچ کر رہے ہیں کہ آیا اس گروہ کا تعلق کسی منظم بین ریاستی گینگ سے تو نہیں ہے۔

گریٹر حیدرآباد میں جی ایچ ایم سی کی خصوصی صفائی

مہم کا آغاز، کمشنر آروی کرن کا اچانک معائنہ

حیدرآباد، (ایجنسیاں) حیدرآباد شہر کو صاف ستھرا بنانے کے مقصد سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن (جی ایچ ایم سی) کی جانب سے پورے شہر میں خصوصی صفائی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس مہم کے پہلے ہی دن میونسپل کمشنر آروی کرن نے قسمت پور اور نارنگی کے علاقوں کا اچانک دورہ کر کے صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ معائنہ کے دوران کمشنر نے فیلڈ لیول کے عہدیداروں کو سخت ہدایات جاری کیں کہ اس خصوصی مہم کو انتہائی مؤثر طریقہ سے نافذ کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ صفائی کے معیار میں کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور عوامی مقامات کو کچرے سے پاک رکھا جائے۔ تمام زونل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جاری اس خصوصی مہم کی خود نگرانی کریں۔ مہم کے پہلے دن فٹ اور ویرجس کی صفائی پر خصوصی توجہ دی گئی تاکہ راگبیروں کو صاف ستھرا راستہ میسر آ سکے۔ سڑکوں پر جاروب کشی، نالوں کی صفائی اور کچرے کی بروقت منتقلی کو یقینی بنانے اضافی عملہ اور مشینری تعینات کی گئی ہے۔ بلدیہ کے حکام نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم میں تعاون کریں اور شہر کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔

تلنگانہ میں سردی کی لہر

کئی اضلاع کے لئے اورنج الرٹ جاری

حیدرآباد، (ایجنسیاں) تلنگانہ میں سردی کی شدت میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات نے آئندہ دو دنوں تک ریاست میں خشک موسم اور شدید سردی کی برقرار رہنے کی پیش قیاسی کی ہے۔ حکام کے مطابق، آج اور کل اقل ترین درجہ حرارت معمول سے کم رہنے کا امکان ہے۔ سردی کی شدید لہر کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے اضلاع کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا ہے: اورنج الرٹ: عادل آباد، کومر، بھیم آصف آباد، منچر، یال، نزل، کامارڈی، میدک اور سنگار پڈی۔ ان اضلاع میں سردی کی شدت سب سے زیادہ رہے گی۔ ایلو الرٹ: حیدرآباد، وقار آباد، جگتیاں، نظام آباد، ورنگل، ہمشکندہ، جنگاؤں، سدی پیٹ، جے شکر بھوپال پی اور نرکار پڈی۔ گزشتہ روز (اتوار) کو ریاست کے کئی حصوں میں درجہ حرارت 10 ڈگری سے نیچے گر گیا۔

सहारनपुर आगमन पर किया जाएगा स्वागत....!!!

अल-अफरोज़ कैटरिंग के निदेशक नौशाद खान को ग्लोबल बिज़नेस अवार्ड, सहारनपुर में खुशी की लहर.....!!!!

सहारनपुर :- अल-अफरोज़ कैटरिंग के निदेशक नौशाद खान को प्रतिष्ठित ग्लोबल बिज़नेस अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर पूरे जनपद में हर्ष और गौरव का माहौल है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर राजनेताओं, समाजसेवियों, उद्यमियों एवं पत्रकारों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। जनपदवासियों ने घोषणा की है कि सहारनपुर आगमन पर नौशाद खान का भव्य स्वागत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में आयोजित भव्य समारोह के दौरान अल-अफरोज़ कैटरिंग के निदेशक नौशाद खान को यह सम्मान प्रदान किया गया। इस मौके पर नौशाद खान के साथ सोहेल खान भी मौजूद रहे।

यह पुरस्कार प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज द्वारा दिया गया। समारोह में फिल्म जगत, व्यवसाय, राजनीति, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी देशभर की कई नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं। अल-अफरोज़ कैटरिंग के मैनेजर राहुल सिंह ने बताया कि आयोजकों के अनुसार यह



पुरस्कार उन विशिष्ट व्यक्तियों को दिया गया, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि नौशाद खान की सफलता के पीछे उनकी पूरी टीम का अहम योगदान है। निदेशक नौशाद खान के साथ कदम से

कदम मिलाकर चलने वाले सोहेल खान ने बताया कि नौशाद खान कभी भी अपनी टीम को स्वयं से अलग नहीं मानते, बल्कि वे टीम के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। और हर उपलब्धि का श्रेय पूरी टीम को देते हैं।

राहुल सिंह ने यह भी बताया कि नौशाद खान की कैटरिंग सेवाएं फिल्मी हस्तियों, राजनेताओं और बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। किसी भी बड़े समारोह में कैटरिंग के लिए नौशाद खान को ही आमंत्रित किया जाता है। मोहल्ला पिलखनतला निवासी नौशाद खान सहारनपुर से दिल्ली एक सपना लेकर गए थे, जिसे पूरा करने में उन्हें लगभग पन्ध्र वर्ष का समय लगा। कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण के बल पर उन्होंने देशभर के नामचीन लोगों को अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का दीवाना बना दिया है। गौरतलब है कि वर्ष २०१५ में भी नौशाद खान को आईफा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो उन्हें फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी एवं आइकॉन अवार्ड भी मिल चुका है। इस पुरस्कार को फिल्म अभिनेत्री मल्लिका अरोड़ा

द्वारा प्रदान किया गया था। इसके अलावा उन्हें कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

नौशाद खान की इस उपलब्धि पर जनपद के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, मेयर डॉक्टर अजय सिंह डीपीसी चेयरमैन जावेद साबरी, उद्यमी औसाफ गुड्डु, वरिष्ठ समाजसेवी व पंजाबी समाज के नेता महेंद्र तनेजा, पूर्व अध्यक्ष नोमान मसूद, मसूद बदर, गुलाम रब्बानी, मुजीब मलिक, निर्यातक अकरम सैफी, जामा मस्जिद के प्रबंधक मौलवी फरीद मजाहिरी, डाक्टर पीडी गर्ग, डॉ. कलीम अहमद, डॉ. राहुल सिंह, रहमान अजीज, इनाम राशिद, अयान खान, आसिफ शम्सी, अतहर उमर, कमर काजमी, गुड्डु, मारुफ बदर, ईशान साबरी, शफाअत अजीम, संजय शर्मा एडवोकेट, डॉ. शाहिद जुबैरी, राव महबूब, ऐनान मसूद, पप्पू खान, हजरत सूफी, चांद रहमान खान, पार्थद फजलुर रहमान, शाहनवाज खान, डॉ. मोनिश, खान समीर, फखरुल, यूसुफ सहित अनेक गणमान्य लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ओर से इमरान प्रतापगढ़ी ने पश की चादर

सांसद प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस अध्यक्ष के संदेश को पढ़ा और दुआ मांगी



अजमेर। ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ओर से सुल्तान-ए-हिंद गरीब नवाज़ की दरगाह पर चादर पेश की गई। बताते चलें कि राजधानी दिल्ली से कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यह पारंपरिक चादर लेकर राजस्थान पहुंचे। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सबसे पहले चादर पेश कर मुल्क की

खुशहाली, अमनो अमान, भाई चारे की दुआ मांगी और जियारत के बाद दरगाह के बुलंद दरवाजा से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जायरीन के नाम भेजे संदेश को पढ़ा। अपने संदेश में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि इंतहाई अकीदत और एहताराम के साथ मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के उर्स मुबारक मौके पर अपनी और पूरी कांग्रेस पार्टी की जानिब से ख्वाजा की बारगाह में चादर रवाना करते

हुए खुद को बेहद खुशकिस्मत पा रहा हूं। ख्याल रहे कि पुरखुलूस जज्बात और अकीदत के साथ सुल्तान उल हिंद के आस्ताना मुबारक पर चादर चढ़ाई जाती है चादर चढ़ाने का यह हसीन मौका हमारे वतन की गंगा-जमुनी तहजीब, कौमी एकता, आपसी भाईचारे, प्यार और मोहब्बत, अदब और रवादारी की अलामत है। इससे पूरी दुनिया में यही पैगाम जाता है कि हिंदुस्तान में कौमी और भाईचारा की जड़े इंतहाई

गहरी हैं। अजमेर में इस विश्व प्रसिद्ध दरगाह पर उर्स मुबारक के मौके पर सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ चादर पेश करने को उनके साथ PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, CLP टीकाराम जूली सहित विधायकगण और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चादर पेश करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भेजा हुआ संदेश पढ़कर सुनाया और देश में भाईचारे के लिये दुआ की।

سری سلیم پراجکٹ میں شیر کی تیراکی

حیدرآباد، (ایجنسیاں) اسے پی کے سری سلیم میں ایک بڑے شیر کی نقل و حرکت نے مقامی افراد اور سیاحوں میں تشویش پیدا کر دی۔ سری سلیم پراجکٹ کے بیک واٹر میں ایک شیر کو بڑے آرام سے تیراکی کرتے ہوئے دیکھا گیا جس کی ویڈیو اب سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ پانی میں راج ہنس کی طرح تیرتے ہوئے اس شیر کا منظر

دیکھنے والوں کو حیران کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سری سلیم بیک واٹر کے راستے آندھرا پردیش سے تلنگانہ ریاست جانے کے لئے دریا کے کرشنا میں تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ خشکی کے ذریعہ طے کرنا پڑتا ہے۔ مقامی افراد اکثر اس راستے کا استعمال کرتے ہیں لیکن اب یہ بات تشویش کا باعث بن گئی ہے کہ ناگر جناساگر۔ سری سلیم ناگیر ریزرو سے شیر بھی اسی آبی راستے کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 2 کلومیٹر تیر کر ایک ریاست سے دوسری ریاست (امرا با د فار ایسٹ ریزرو تلنگانہ) کی طرف جا رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تقریباً ایک ہفتہ قبل آتما کوڑو ویشن کے سنگمیشورم کے قریب شیر تیر کر امر آباد کی طرف گیا۔ محکمہ جنگلات نے شیر کے بچوں کے نشانات کی بنیاد پر شناخت کی ہے کہ وہ براہ راست جنگل میں جانے کے بجائے کولہا پور منڈل کے کھیتوں میں گھوم رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر محکمہ جنگلات کے حکام نے دریا کے قریبی علاقوں کے افراد، مائی گیروں اور کسانوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ آتما کوڑو کے ڈپٹی ڈائریکٹر کنیش نے بتایا کہ شیر کی نقل و حرکت پر کوئی نظر رکھی جا رہی ہے اور جب تک وہ محفوظ طریقہ سے دوبارہ جنگل میں داخل نہیں ہو جاتا نگرانی جاری رہے گی۔

تلنگانہ اسمبلی میں کانگریس اور بی آر

ایس میں نوک جھونک، کارروائی ملتوی

حیدرآباد، (ایجنسیاں) تلنگانہ اسمبلی کے سرمانی اجلاس کے پہلے دن حکمران جماعت کانگریس اور اصل اپوزیشن بی آر ایس ارکان میں بحث و تکرار کے بعد اسپیکر جی پرسادکار نے ایوان کی کارروائی 2 جنوری تک ملتوی کر دی۔ آج صبح 10.30 بجے اجلاس کا آغاز قومی ترانہ اور تعزیتی قراردادوں سے ہوا جس میں سابق وزیر ورنن اسمبلی (سورہ پیٹ و تنگارتی) رام ریڈی دامودر ریڈی اور چنپوڑلہ کے سابق ایم ایل اے کوئڈا لکھنار ریڈی کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا اور ایوان نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تعزیتی قراردادوں کے بعد وقفہ صفر کے دوران مختلف حلقوں کے ارکان اسمبلی نے عوامی مسائل ایوان میں پیش کیا تاہم اس دوران حکمران جماعت کانگریس اور اپوزیشن بی آر ایس کے ارکان کے درمیان کئی نوک جھونک اور گرما گرم بحث بھی دیکھنے کو ملی۔ اہم بلز کی پیشگی اور بحث کے بعد اسپیکر نے اعلان کیا کہ اب اسمبلی کا اجلاس 2 جنوری کی صبح 10 بجے دوبارہ شروع ہوگا۔ اس وقفہ کے دوران مختلف سیاسی جماعتیں اپنی حکمت عملی تیار کریں گی تاکہ اگلے سیشن میں عوامی مسائل اور مجوزہ بلز پر تفصیلی بحث کی جاسکے۔

تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں

ایرپورٹ کی تعمیر کے لئے پیشرفت

حیدرآباد، (ایجنسیاں) تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں مجوزہ ایرپورٹ کی تعمیر کے لئے پیشرفت ہوئی ہے اور اب اس پراجکٹ کیلئے ایریا میننگ کو کلیدی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ میننگ تفصیلی پراجکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) کی تیاری اور اراضی کے حصول کے عمل کی بنیاد بنے گی۔ توقع ہے کہ وزارت دفاع اور ایرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا (اے اے آئی) کے حکام ڈی پی آر کو حتمی شکل دینے سے پہلے علاقہ کا مکمل سروے اور میننگ شروع کریں گے۔ اس کام کے دوران ماہرین رہائشی علاقوں، زرعی اراضی، ہائی ٹیشن بجلی کے ٹاورس اور اراضیات کی دستیابی جیسے تکنیکی پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے۔ تلنگانہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ عادل آباد ایرپورٹ کو ایک ملٹی آپریشنل فیسبلٹی کے طور پر تیار کیا جائے جہاں کارگو سروس، انڈین ایئر فورس کی تربیتی سہولیات اور عام شہریوں کے لئے شہری ہوابازی کے طیارے بیک وقت دستیاب ہوں۔ عادل آباد کے بی جے پی ایم پی جی ناگیس کے مطابق مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے مشترکہ اقدامات کی وجہ سے اس تجویز کو تقویت ملی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی تلنگانہ کی مستقبل کی ہوابازی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اس ایرپورٹ کی ترقی میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایم پی ناگیس نے واضح کیا کہ اراضی کا حصول ایک حساس اور تکنیکی مرحلہ ہے کیونکہ اس کے لئے کسانوں کی رضامندی اور معاوضہ کی شرح طے کرنا ضروری ہے۔ حکومت تلنگانہ نے اس مقصد کے لئے 1700 ہیکٹر اراضی حاصل کرنے کی خاطر پہلے ہی جی او 73 جاری کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کے دورہ کے بعد اس پراجکٹ میں مزید تیزی آئی ہے۔ ایرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا (اے اے آئی) جلد ہی ٹرمینل بلڈنگ، رن وے اور دیگر بنیادی ڈھانچہ کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گی جبکہ میننگ کا کام ریاستی حکومت، فضائیہ اور وزارت دفاع کے اشتراک سے جاری رہے گا۔

اساتذہ نہیں کریں گے کتوں کی گنتی، دہلی حکومت نے افواہوں کی تردید کی



طریقہ سے شائع کی گئی تھیں، جو اسے اساتذہ کے آوارہ کتوں کی گنتی کے کام سے منسلک کرتی تھیں۔ حقیقت میں حکومت نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ اساتذہ یونین کا احتجاج کیا ہے کہ یونین نے اس خبر پر بھی احتجاج کیا ہے کہ دارالحکومت کے سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کو آوارہ کتوں کی گنتی کا کام سونپا گیا ہے۔ یونین نے کہا کہ ایک استاد کا بنیادی کردار طلباء کو تعلیم دینا اور بہتر تعلیم فراہم کرنا ہے، نہ کہ ایسے کاموں کو انجام دینا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اساتذہ کو ان کی شراکت اور احترام کے مطابق کام سونپے جانے چاہئیں، لیکن بدقسمتی سے اس معاملے میں اساتذہ کو غیر ضروری ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

مقرر کریں تاکہ طلباء کو آوارہ کتوں سے بچایا جاسکے۔ اس افسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکول کے احاطے میں سیکورٹی کی نگرانی کرے اور کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں متعلقہ محکموں کے ساتھ رابطہ کرے۔ تاہم، یہ معلومات غلط

بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت صرف طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جاری کی گئی ہے۔ نوڈل آفیسر کی تقرری کے انتظامات دہلی حکومت کے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اسکولوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنے اساتذہ میں سے ایک نوڈل افسر

نئی دہلی: دہلی کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کو آوارہ کتوں کی گنتی کا کام سونپنے کی خبر نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ دہلی حکومت نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے ایسی خبروں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حکومتی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی اساتذہ کو ایسی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ سرکلر کا مقصد: طلباء کی حفاظت ذرائع کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن نے دہلی میں آوارہ کتوں سے عام لوگوں اور خاص طور پر طلباء کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی ہدایات کے جواب میں ایک سرکلر جاری کیا۔ اس سرکلر کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ اسکول کے احاطے میں کوئی آوارہ کتا موجود نہ ہو، تاکہ طلباء کی حفاظت سے سمجھوتہ نہ ہو۔

تلنگانہ کے دو طالبات امریکہ میں سڑک حادثہ میں ہلاک

حیدرآباد، (ایجنسیاں) تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد کی دو طالبات کمیٹیورینا، امریکہ میں پیش آئے سڑک حادثہ میں ہلاک ہو گئیں۔ مہلک لڑکیوں کی شناخت 25 سالہ بیگھنارانی اور 24 سالہ کے بھوانا کے طور پر کی گئی ہے جو ضلع محبوب آباد کے منڈل گارلا کی رہنے والی تھیں۔ دونوں طالبات نے حال ہی میں اپنی ایم ایس کی

ڈگری مکمل کی تھی اور وہ امریکہ میں روزگار کے بہتر مواقع تلاش کر رہی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک سیر و تفریح سے واپس لوٹ رہی تھیں۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی کار اچانک سڑک سے پھسل کر ایک گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں دونوں کی موت ہو گئی۔

وزیر داخلہ شاہ آسام میں کئی منصوبوں کا افتتاح کریں گے



جس میں پانچ ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ مسٹر شاہ ریاست کے شہید اسمارک گارڈن بھی جائیں گے، جہاں وہ آسام تحریک کے 860 شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے بعد وزیر

گواہٹی (ایجنسیاں) مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پیر کے روز آسام کے دارالحکومت گواہٹی پہنچیں گے، جہاں وہ کئی اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ مسٹر شاہ اٹلی جنت سٹی سروسز سسٹم (آئی سی ایس ایس) کا افتتاح کریں گے، جو تحفظ اور قانونی نظم و نسق کو مضبوط بنانے کے مقصد سے شہر بھر میں نصب سی سی ٹی وی نیٹ ورک ہے۔ آئی سی ایس ایس کے تحت یہ نظام 2,000 سے زائد سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کرے گا، جس سے ریاست میں سلامتی اور ہنگامی رد عمل کے نظام کو بہتر بنایا جاسکے گا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر داخلہ نے

وزیر اعلیٰ دھامی نے تریپورہ کے طالب علم انجیل چکما کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا

بعد، 27 دسمبر کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب تک اس معاملے میں پانچ ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ ایک مفروضہ ملزم کی تلاش



وزیر اعلیٰ دھامی نے کہا کہ ہماری حکومت اس معاملے پر پوری سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کے غیر انسانی واقعات ریاست میں کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد اب تک پانچ ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔

جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ دھامی نے کہا کہ ہماری میں کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد اب تک

دہرادون (ایجنسیاں) اترکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پتیکر سنگھ دھامی نے پیر کے روز دہرادون میں وزیر تعلیم طالب علم انجیل چکما کی موت پر ان کے لواحقین سے فون پر بات چیت کی اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ مسٹر دھامی نے اس انتہائی افسوسناک واقعے پر گہری تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ قصور واروں کے خلاف سخت ترین کارروائی میں لائی جائے گی۔ ریاست کے دارالحکومت کے سیلا کی علاقے کے ایک نجی ادارے میں زیر تعلیم تریپورہ کے طالب علم انجیل چکما پر حملہ آوروں نے چاقو سے حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا تھا۔ سترہ دنوں تک ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے